राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 304

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 11 अप्रैल 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 14

नौसेना प्रमुख ने कहा, सामरिक साजो-सामान को कोरोना से बचाने की जरूरत

>>3

कोरोना मीटर

(स्रोत: वर्ल्डोमीटर्स डॉट इंफो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

	विश्व	अमेरिका	स्पेन	भारत	4 अप्रैल की स्थिति	वृद्धि दर	दिल्ली
कुल केस	16,23,175	4,69,464	1,57,022	7,540	3,017	149%	903
मौतें	97,236	16,711	15,843	248	80	210%	14
स्वस्थ हुए	3,66,409	25,937	55,668	677	192	252%	26

भारत के प्रमुख राज्य

राज्य	केस	मौतें
महाराष्ट्र	1574	110
तमिलनाडु	911	8
राजस्थान	561	3
तेलंगाना	487	7
मध्य प्रदेश	483	16
उत्तर प्रदेश	436	4
आंध्र प्रदेश	381	6
केरल	364	2
अन्य	1440	78

रात 11:30 बजे तक

अन्य प्रमुख देश

देश	इटली	जर्मनी	फ्रांस
केस	1,43,626	1,18,235	1,17,749
मौतें	18,279	2,607	12,210

नोट: कोरोना से प्रभावित लोगों के संदर्भ में आंकड़े उल्लिखित दो स्रोतों के अतिरिक्त जागरण न्यूज नेटवर्क के रूप में अन्य माध्यमों से भी लिए गए हैं। अत: तालिका तथा दैनिक जागरण के इस अंक में प्रकाशित सामग्री में आंकड़ों का अंतर संभव है।

दिल्ली में जमातियों के कारण बिगड़े हालात

बढ़ती चिंता ▶ राजधानी में एक दिन में 183 नए मामले सामने आए, इनमें 154 जमाती

देशभर में रिकॉर्ड आठ सौ से ज्यादा नए मामले मिले, संक्रमितों की संख्या साढ़े सात हजार के पार पहुंची

जेएनएन, नई दिल्ली

मुंबई के साथ ही दिल्ली व दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु देश में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। मुंबई में आंकड़ा एक हजार के करीब पहुंच गया है वहीं दिल्ली और तमिलनाडु में भी इनकी संख्या नौ-नौ सौ को पार कर गई है। इन दोनों ही राज्यों में हालात बिगाड़ने में तब्लीगी जमात के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। शुक्रवार को ही दिल्ली में 183 नए मामले सामने आए, जिनमें से 154 तब्लीगी हैं यानी करीब 85 प्रतिशत। अगर पूरे देश की बात करें तो आठ सौ से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमितों का आंकड़ा साढ़े सात हजार को पार कर गया है, जबकि 21 मौतों के साथ मृतकों की संख्या भी ढाई सौ के करीब हो गई है।

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक 6,761 संक्रमित सामने आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। 516 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आंकड़ों में अंतर पर अफसरों का कहना है कि राज्यों की संबंधित इकाइयों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़े मिलने में देरी के कारण यह अंतर रहता है। कई निजी एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े लेती हैं।

राज्य सरकारों से मिली सूचनाओं के मुताबिक, शुक्रवार को महाराष्ट्र में 10, मध्य प्रदेश में चार, गुजरात व दिल्ली में दो-दो और असम, पंजाब व तमिलनाडु में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। देश में अब तक इस महामारी ने 248 लोगों की जान ले ली है, जबकि, 830 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी 7,540 पर पहुंच गया है। इनमें 70 से ज्यादा विदेशी और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके 677 व्यक्ति भी शामिल हैं।

● तमिलनाडु और दिल्ली बने हॉटस्पॉट, महाराष्ट्र में महामारी से 110 लोगों की मौत

दिल्ली के निजामुद्दीन में हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित मस्जिद के आसपास के इलाके में शुक्रवार को सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इसी मस्जिद में तब्लीगी जमात के लोग ठहरे हुए थे। प्रेट्र

राजधानी में 64.67 फीसद संक्रमित जमाती

राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ा है और इसमें तब्लीगी जमात वालों का कितना बड़ा हाथ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन दिन में ही 327 मामले सामने आए हैं। राजधानी में अभी तक संक्रमितों की संख्या 903 है, जिनमें से 584 तब्लीगी जमात के लोग हैं। कुल कोरोना पीड़ितों में जमातियों की यह संख्या 64.67 फीसद बैठती है।

धारावी में बढ़े मामले

महाराष्ट्र में शुक्रवार को 210 नए मामले सामने आए और राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,574 हो गई। मुंबई में ही 132 नए मामले मिले हैं, जिनमें 11 केस धारावी के हैं, जो सबसे चिंता की बात है। लगभग 15 लाख की आबादी वाली एशिया की इस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में अब तक 28 संक्रमित केस मिल चुके हैं, जिनमें से दो की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 993 हो गई है।

गुजरात में और पांच संक्रमित

गुजरात में 116 नए केसों संग संक्रमितों की संख्या 378 हो गई है, जिनमें पांच जमाती भी हैं। नए मामलों में 17 वडोदरा में एक ही इलाके में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 नए केस मिले हैं, जिनमें आठ जमाती हैं और कुल संक्रमित 436 हो गए हैं।

तमिलनाडु में वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा नौ सौ के पार

तमिलनाडु में 77 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 911 हो गया है। इनमें से भी ज्यादातर तब्लीगी हैं। 10 दिन पहले तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 50 से कुछ ज्यादा थी। लेकिन दिल्ली से तब्लीगी क्या लौटे, महामारी को साथ लेते गए और राज्य के हालात ही बदल गए। कर्नाटक में 10 नए केस मिले हैं और संक्रमित 207 हो गए हैं। जबकि, आंध्र प्रदेश में दो नए केस के साथ आंकड़ा 381 हो गया है। तेलंगाना में भी 16 नए मामले आए हैं और कुल संक्रमित 487 हो गए हैं। केरल में सात मरीजों के साथ अभी तक कुल 364 संक्रमित सामने आए हैं। नए मामलों में दो तब्लीगी जमात से जुड़े हैं। साथ ही कुल संक्रमितों में स्वस्थ हो चुके 124 लोग भी शामिल हैं।

एंटीबॉडी आधारित 16 में से आठ टेस्ट संतोषजनक : आइसीएमआर

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने शुक्रवार को बताया कि एंटीबॉडी आधारित 16 रैपिड टेस्ट की पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी (एनआइवी) ने पुष्टि की है जिनमें से अभी तक आठ संतोषजनक पाए गए हैं।

पंजाब ने एक मई तक बढ़ाया कर्फ्यू

नई दिल्ली : कोरोना वायरस से भयावह होते हालात को देखते हुए ओडिशा के बाद दूसरे राज्य भी अपने स्तर पर एहतियाती पाबंदियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। (पेज-5)

राजस्थान में एक दिन में 98 केस पेज>>6

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा-अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ आइसीएमआर की रिपोर्ट और कुछ राज्यों के दावों से सहमत नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय

▶ कहा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ तो सरकार खुद करेगी लोगों को सतर्क

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत कई राज्यों की ओर से कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज तीन में पहुंचने के दावे के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इससे इन्कार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने साफ कहा है कि कोरोना देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में नहीं पहुंचा है। यदि ऐसा हुआ तो सरकार खुद लोगों को इसके प्रति आगाह करेगी। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के एक अध्ययन में भी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने के संकेत मिले हैं।

लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश में 16,002 कोरोना के टेस्ट हुए हैं, जिनमें 320 ही पॉजिटिव पाए गए हैं जो टेस्ट किए गए मामलों का 0.2 फीसद है। इससे साफ है कि वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता तो बड़ी संख्या में मरीज पाए जाते। अग्रवाल के अनुसार आइसीएमआर ने सांस से संबंधित बीमारियों के गंभीर से रूप से पीड़ित मरीजों की रैंडम सैंपलिंग कर कोरोना वायरस का टेस्ट किया, उसमें भी 1.8 फीसद मामले ही पॉजिटिव आए हैं। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि ये पॉजिटिव मामले भी उन्हीं इलाकों से आए जहां पहले से कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। जिन इलाकों में कोरोना का मामला नहीं था, वहां एक भी मामला नहीं मिला।

लव अग्रवाल फाइल फोटो

बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीजों का मिलना इसका सुबूत नहीं : लव अग्रवाल ने बिना ट्रैवल या कांटेक्ट हिस्ट्री वाले कोरोना मरीजों के सामने आने को कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सुबूत मानने से इन्कार कर करते हुए कहा, यह सही है कि आइसीएमआर की रिपोर्ट व राज्य सरकारों के कई मामलों में मरीज की कोई ट्रैवल या कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि हमें मरीज की कांटेक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने की और कोशिश करनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जहां मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, वहां कांटेक्ट ट्रेसिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है।

अभी चेन रिएक्शन के संकेत नहीं : लव अग्रवाल ने कहा, कोरोना वायरस एक आदमी से दो में दो से चार और चार से 16 में फैलता है। भारत में मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अभी चेन रिएक्शन नहीं है।

अब भारत में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पेज>>6

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी प्रामाणिक सूचना पाई जा सकती है। कृपया नंबर दर्ज करके वाट्सएप पर सिर्फ नमस्कार का संदेश भेजें। तुरंत एक मेन्यू आएगा, जिसके अनुसार वांछित जानकारी ली जा सकती है।

who:+41 798931892

mygov: +919013151515

कोरोना को हराना है

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 13 देशों को दी जाएगी • पेज 4

योगी ने 4.81 लाख गरीबों के खाते में भेजे एक-एक हजार रुपये • पेज 5

डब्ल्यूएचओ के साथ वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी • पेज 6

सरोकार

500 रुपये में सिर से लेकर पांव तक सुरक्षा

सिवान : बिहार के एक डॉक्टर ने महज 500 रुपये में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट बनाई है, जिसे अन्य कंपनियां दो से ढाई हजार में बेच रही हैं। उत्तर प्रदेश ने एक लाख किट का ऑर्डर दिया है। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

घर बैठे ही पढ़ाई को और बेहतर बनाने में जुटी सरकार

नई दिल्ली: कोरोना से बचाव का कारगर उपाय सामने आने तक सरकार छात्रों को घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही 'पढ़े भारत ऑनलाइन' नाम से मुहिम भी शुरू की है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

मप्र, बंगाल और छत्तीसगढ़ में निकला लॉकडाउन का जनाजा

नई दिल्ली : कुछ लोग लॉकडाउन का ही जनाजा निकालने पर तुले हैं। मप्र और बंगाल में जहां सामूहिक नमाज पढ़ी गई। वहीं, छत्तीसगढ़ में जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

कच्चे तेल के दाम को फिर मिलेगी धार

मैक्सिको सिटी: 60 फीसद से ज्यादा टूट चुके कच्चे तेल के दाम को फिर धार मिलने वाली है। तेल उत्पादकों व निर्यातकों के संगठन ओपेक और चुनिंदा देशों ने शुक्रवार की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की बड़ी बाधा पार कर ली।

लॉकडाउन पर आज फैसले के आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

▶ कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में

ओडिशा के बाद पंजाब सरकार की ओर से खुद ही अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद वैसे तो स्पष्ट है कि कोरोना के बड़े खतरे से बचने के लिए लगभग पूरा देश लॉकडाउन विस्तार के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम इसकी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। आसार हैं कि डेढ़ से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती भी होगी।

गत चार-पांच दिनों में पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वृद्धि तेज हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी मरीज आ रहे हैं जहां अब तक सबकुछ नियंत्रित दिख रहा था। कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्री ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जता रहे हैं। जाहिर है कि यह देश के लिए नाजुक दौर है। ऐसे में शनिवार को पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की होने वाली वीडियो कांफ्रेसिंग बहुत अहम है।

बदले हालात में गंभीर चुनौती : पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन से बाहर आने के रास्तों पर सुझाव मांगा था। उस वक्त तक लग रहा था कि 14 अप्रैल के बाद चरणबद्ध तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है, लेकिन दो दिनों में कोरोना की चुनौती गंभीर हुई है। बड़े शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। लगभग कोरोना मुक्त पूर्वोत्तर में भी पाजिटिव मरीज आ रहे हैं। बिहार में एकबारगी दो दर्जन मरीज सामने आए हैं। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि शनिवार सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में शायद ही कोई मुख्यमंत्री लॉकडाउन हटाने की बात करे। ध्यान रहे कि दो दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने भी पीएम के लाकडाउन के फैसले से एकजुटता जताई थी और आगे का फैसले पर भी एकमत रहने का भरोसा दिया था।

पीएमओ ने की समीक्षा : शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में पूरी तैयारी की समीक्षा की गई। पर्सनल प्रोटेक्शन किट व अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता का निर्देश दिया गया। गरीबों के लिए चलाई रही योजनाओं की भी समीक्षा हुई। बैठक में गृहमंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों की क्षेत्रीय भाषा में जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। कृषि कार्य में जुटे लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रहते हुए काम करने की सहूलियत देने पर चर्चा हुई।

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

पीएम कर सकते हैं देश को संबोधित

संभवत: शनिवार शाम ही पीएम फिर से देश को संबोधित कर सकते हैं। पूरे देश के मत को सामने रखते हुए बता सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण भारत कोरोना की गति को थामने में कामयाब रहा है। अब उसे पूरी तरह रोकने की लड़ाई बाकी है। केंद्र की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि इस महामारी से जंग के लिए केंद्र पूरा खर्च अपने ऊपर लेगा।

धार्मिक जमावड़े की मंजूरी न दें राज्य : केंद्र

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी की जरूरत पर दिया जोर

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश के विभिन्न भागों में इस महीने मनाए जाने वाले त्योहारों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 दिन के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे किसी भी सामाजिक या धार्मिक जमावड़े और जुलूस की अनुमति न दें। साथ ही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ सोशल मीडिया पर उचित निगरानी बनाए रखें। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर सभी तरह का आवागमन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाइडलाइंस के संबंधित प्रावधानों का व्यापक पैमाने पर प्रसार किया जाना चाहिए। लॉकडाउन के नियमों का किसी भी रूप में उल्लंघन किए जाने पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाए सीमा सुरक्षा बल : अमित शाह

अमित शाह फाइल फोटो

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर सभी तरह का आवागमन रोकने के साथ ही सीमांत इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बिना बाड़ (तारबंदी) वाले इलाकों में विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि कोई भी वहां से प्रवेश न कर सके। शाह ने सीमांत क्षेत्रों में ग्रामीणों और किसानों को कोविड-19 के प्रति जागरूक बनाने को भी कहा है। गृह मंत्री ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया वे सुनिश्चित करें कि कोई अनजाने में भी सीमा पार नहीं करने पाए।

लॉकडाउन के बारे में राज्यों से राय भी मांगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 दिनों के लॉकडाउन पर राज्यों से राय भी मांगी है। इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या लॉकडाउन के दौरान लोगों और सेवाओं की अधिक श्रेणियों को छूट प्रदान करने की आवश्यकता है। संकेत हैं कि सरकार लॉकडाउन की अवधि दो हफ्ते और बढ़ा सकती है। राज्यों से लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। बिहार समेत कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे में गृह मंत्रालय को लिखा भी है। राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने समेत कई सुझाव दिए हैं।

अहम फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, परिवार चलाने वाली गृहिणी की तुलना घरेलू सहायिका से नहीं की जा सकती, उसकी आय के आधार पर नहीं किया जा सकता मुआवजे का फैसला

अमूल्य है घर संभालने वाली महिला का योगदान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▶ ट्रिब्यूनल ने तय किया था 1,17,500 रुपये मुआवजा, हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 5,56,000 रुपये किया

▶ कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को किया खारिज, कहा-गृहिणी परिवार का चौबीस घंटे ध्यान रखती है

महिलाएं किसी भी परिवार का आधार होती हैं, लेकिन कई बार उनके योगदान को कम कर आंकने की गलती हो जाती है। ऐसी ही एक गलती को सुधारते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गृहिणी का अपने परिवार के लिए योगदान अमूल्य होता है। उसकी घरेलू सहायिका से तुलना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से तय 1,17,500 रुपये मुआवजे को नाकाफी बताते हुए बढ़ाकर 5,56,000 रुपये कर दिया।

मूल रूप से करनाल के रहने वाले पति-पत्नी स्कूटर से जा रहे थे। पंजाब में लुधियाना के पास उनके स्कूटर को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी और पति घायल हो गया था। बाद में पति ने मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए अर्जी लगाई। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि याची पत्नी के साथ जा रहा था, तभी एक ट्रक ने उसके स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर से वह दूर जाकर गिरा और पीछे बैठी उसकी पत्नी ट्रक के नीचे आ गई। ट्रिब्यूनल ने महिला की मौत पर मुआवजे की गणना घरेलू सहायिका को होने वाली आय को बनाया। ट्रिब्यूनल ने दो हजार रुपये मासिक के आधार पर 1,17,500 रुपये मुआवजा तय किया। पति ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली, लेकिन बीमा कंपनी ने इसका विरोध किया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने आय का आकलन सही किया है। इससे ज्यादा होने पर यह न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा हो जाता है। महिला गृहिणी थी और सिलाई का काम करती थी, इसलिए उसकी आय दो हजार रुपये मानना उचित है। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फार्मूले और बीमा कंपनी की दलील से प्रबल असहमति जताते हुए कहा कि यह गृहिणी और पीड़ित परिवार के साथ भद्दा मजाक है। कोई महिला अपने पति, बच्चे और पूरे परिवार का ध्यान रखती है और 24 घंटे घर के लिए समर्पित रहती है। इस दौरान वह स्वयं अपना भी ध्यान नहीं रख पाती। आप उसकी तुलना एक घरेलू सहायिका से कैसे कर सकते हैं? इसी के साथ याची की अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को 5,56, 000 रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया।

मशहूर शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद का निधन

जासं, गुरुग्राम : मशहूर शास्त्रीय व गजल गायिका पद्मश्री शांति हीरानंद का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं।

शांति हीरानंद। फाइल सौ. सांस्कृतिक संस्था सनतकदा

प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर की प्रमुख शिष्या रहीं शांति हीरानंद गैस्ट्रोएंट्राइटिस से पीड़ित थीं। तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार देर रात उन्हें गुरुग्राम स्थित फोर्टिस अस्पताल के आइसीयू में शिफ्ट कराया गया, जहां सुबह करीब तीन बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। दोपहर बारह बजे उनके पार्थिव शरीर को डीएलएफ फेज थ्री स्थित आवास पर लाया गया। वह बेटे निश्चिंत के साथ यहां रह रही थीं। 2007 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। शांति हीरानंद के निधन से संगीत जगत शोक में है।

याद रहेंगी बेगम की बिदुटन : पेज-7

पाकिस्तान ने तोड़ा संघर्ष विराम, भारत ने मार गिराए पांच सैनिक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ नीलम घाटी में आतंकियों का लांचिंग पैड तबाह किया

▶ पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को भी नुकसान

नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर पाकिस्तानी सेना को फिर मुंह की खानी पड़ी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में नीलम घाटी में पाकिस्तान के पांच सैनिक मार गिराए गए। पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उसका एक लांचिंग पैड भी तबाह कर दिया। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, सीमा पार से हुई फायरिंग में भारतीय क्षेत्र में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भी शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

बता दें कि केरन में तैनात जवानों ने शुक्रवार सुबह एलओसी के पार नीलम घाटी के दुदनियाल व थेजियां इलाके में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां देखीं। पाकिस्तानी सेना का एक दस्ता एलओसी के अगले हिस्से की तरफ आया था। इसके आधार पर संबंधित फील्ड कमांडरों को पाक की तरफ से बैट कार्रवाई और घुसपैठ के प्रयास की आशंका हुई। इस पर सभी अग्रिम चौकियों को सचेत कर दिया गया। दोपहर साढ़े बारह बजे पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलाबारी शुरू कर दी। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। जवाब में भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

भारत ने तोपों और मोर्टार का किया प्रयोग पेज>>12

36.2 डिग्री सेल्सियस रहा शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गर्मी और तापमान में अब लगातार इजाफा ही होने की संभावना है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 11 अप्रैल 2020

ऑपरेशन शील्ड ने दिलशाद गार्डन में रोका कहर

राहत ▶ सऊदी अरब से आईं महिला को सबसे पहले हुआ था कोरोना, फिर उनसे सात अन्य भी हो गए थे पीड़ित

केजरीवाल सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान चलाने की घोषणा की है

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को रोकने के लिए जिस ऑपरेशन शील्ड को बड़े स्तर पर शुरू करने की गुरुवार को घोषणा की है, वह दिलशाद गार्डन में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुका है। वहां 123 मेडिकल टीमों के माध्यम से 15 हजार लोगों की 15 दिन घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की गई। ऑपरेशन सफल रहा है और कोरोना के मरीज आने बंद हो गए हैं। इस सफलता के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस ऑपरेशन को दिल्ली भर में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में लागू करने का फैसला लिया है।

यह था मामला : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिलशाद गार्डन की रहने वाली एक महिला और उनके बेटे में सऊदी अरब से लौटने पर कोरोना पाया गया था। महिला के अलावा मोहल्ला क्लीनिक डाक्टर समेत सात लोग भी कोरोना पीड़ित हो गए। इसके बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोरोना के फैलने का डर था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड चलाया गया। अब इस क्षेत्र को कोरोना मुक्त कर लिया गया है।

17 मार्च को महिला में कोरोना की हुई थी पुष्टि : शाहदरा के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. एस के नायक ने बताया कि दिलशाद गार्डन में रहने वाला एक व्यक्ति सऊदी अरब में रहता है। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर उनसे मिलने सऊदी अरब गई थीं। वह महिला बेटे के साथ गत 10 मार्च को सउदी अरब से वापस लौटीं। 12 मार्च को इन महिला को बुखार और खांसी की शिकायत हुई। वह पुरानी सीमापुरी स्थित एक मोहल्ला क्लीनिक में दवा लेने गईं। मगर आराम न मिलने पर 15 मार्च को वह जांच कराने जीटीबी अस्पताल गईं, जहां उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। जिस पर उन्हें आरएमएल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जांच के बाद 17 मार्च को महिला में कोरोना की पुष्टि हुई।

संपर्क में आने वाले सात अन्य भी हुए कोरोना पीड़ित : महिला से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह तब तक मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर समेत 81 लोगों से मिल चुकी थीं।। ऐसे में उनके संपर्क में आने वाले डॉक्टर समेत सात अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।

सीसीटीवी का सहारा लिया : महिला से पूछताछ में पता चला कि उनके साथ उनका बेटा भी गया था तो उससे भी पूछताछ की गई कि वह किन-किन लोगों से मिला। लेकिन उससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में वह जिन-जिन लोगों से मिलता दिखा उन सभी को क्वारंटाइन किया गया।

शाहदरा जिलाधिकारी से मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया ऑपरेशन शील्ड : दिलशाद गार्डन में कोरोना पीड़ितों के बढ़ते मामले देखकर सरकार ने तत्काल मेडिकल टीमों का गठन किया। साथ ही शाहदरा के जिलाधिकारी से मिलकर ऑपरेशन शील्ड चलाने का निर्णय लिया। पुलिस की मदद से दिलशाद गार्डन व पुरानी सीमापुरी इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पुरानी सीमापुरी को इसलिए सील किया गया, क्योंकि महिला के संपर्क में आने से पुरानी सीमापुरी के मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर भी कोरोना से पीड़ित हो गए थे।

घर-घर जाकर 15 हजार लोगों की गई स्क्रीनिंग : दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई 123 मेडिकल टीम में एक डॉक्टर व दो मेडिकल स्टाफ शामिल थे। इन टीमों को 50-50 घरों की स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीमों ने दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी के 4032 घरों में जाकर 15 हजार से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की। जिन्हें कोई परेशानी थी, उन्हें तत्काल एंबुलेंस से आरएमएल अस्पताल भेजा गया।

डॉ. एस के नायक का कहना है कि 15 से अधिक दिनों की लगातार मेहनत और लगन का परिणाम सकारात्मक निकला है। दिलशाद गार्डन और पुरानी सीमापुरी में एक भी कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। फिर भी दिल्ली सरकार लगातार वहां के 15 हजार लोगों को फोन कर कोरोना के संबंध में जानकारी ले रही है। इस क्षेत्र पर लगातार नजर है।

केंद्र से मिलीं चार हजार पीपीई किट : सत्येंद्र जैन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सत्येंद्र जैन। फाइल

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमें केंद्र सरकार से लगभग 4000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट मिल गई हैं। इसके अलावा एक लाख रैपिड किट भी मांगी गई है, ये किट भी एक-दो दिन में आ जानी चाहिए। किट आते ही सबसे पहले तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों का टेस्ट किया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना की सबसे पहले टेस्टिंग कोविड-19 अस्पतालों में की जाएगी। दिल्ली में पहचाने गए हॉटस्पॉट में हम निवासियों की डोर-टू-डोर मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। निजामुद्दीन क्षेत्र में 6,000 घरों में भी स्क्रीनिंग की गई है। यहां एक व्यक्ति में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है।

गंभीर ने लोकनायक अस्पताल को दी एक हजार पीपीई किट : पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने लोकानयक अस्पताल को एक हजार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट उपलब्ध कराई हैं। इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह और भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएंगे।

उन्होंने कहा कि हमने वाद निभा दिया है, अब मुख्यमंत्री को दिल्ली वालों से किया वादा निभाना चाहिए। पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कोरना संकट से निपटने में फंड देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में गंभीर ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए अपने सांसद निधि से 50 लाख रुपये और देने की घोषणा की थी। पहले भी वह 50 लाख रुपये देने की घोषणा कर चुके थे।

प्रदूषण से पीछा छूटा, छह साल का रिकॉर्ड टूटा

देशभर में लॉकडाउन के चलते प्रदूषण बिल्कुल साफ हो गया है। लोग खुली हवा में सांस लेकर अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। मिंटो रोड, कनॉट प्लेस में लॉकडाउन में पसरा सन्नाटा और यहां पर सिर्फ शांति पसरी है। ध्रुव कुमार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- 2014 से मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में कभी नहीं रही इतनी स्वच्छ हवा
- एक पखवाड़े से भी ज्यादा समय से अच्छा या सामान्य श्रेणी में चल रहा हवा का स्तर

नीला आसमान, चटक धूप, धूल का नामोनिशान नहीं। जहां तक नजर जाए, एकदम साफ दृश्य, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट...लॉकडाउन के इस दौर में कुछ ऐसी ही हो गई है दिल्ली की पहचान। यह वही दिल्ली है जो कुछ दिन पहले तक विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 10 शहरों में शुमार थी। आज यहां की हवा इतनी साफ है कि श्वास और अस्थमा के रोगी भी सुकून महसूस कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के शहरों में भी इन दिनों कमोबेश ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। घटे प्रदूषण के बीच साफ हवा ने पिछले छह साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

मौजूदा समय में हवा से पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफी कम हो गई है। एयर इंडेक्स भी अच्छा या सामान्य श्रेणी में बना हुआ है। सुखद यह भी है कि प्रदूषण मुक्त हवा की यह स्थिति भी गत 22 मार्च से बनी हुई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफर इंडिया के मुताबिक सबसे अधिक कमी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आई है। पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों के जलने पर उत्पन्न होने वाला यही प्रदूषक तत्व फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से न तो वाहन चल रहे हैं और न ही औद्योगिक इकाइयां। प्रदूषक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 भी 55 से 60 फीसद तक कम हो गया है।

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर का एयर इंडेक्स

शहर	एयर इंडेक्स
दिल्ली	118
फरीदाबाद	117
गाजियाबाद	115
ग्रेटर नोएडा	101
गुरुग्राम	104
नोएडा	93

बीते छह सालों की स्थिति : दिल्ली-एनसीआर का एयर इंडेक्स इस समय बीते छह साल में सबसे बेहतर है। 2014 में मार्च के अंतिम और अप्रैल के पहले सप्ताह का एयर इंडेक्स 130 से 180 के बीच रहा था। इसी तरह 2015 में यह 90 से 140 के बीच रहा था। 2016 में स्थिति खराब थी, क्योंकि इस साल एयर इंडेक्स 115 से 190 के बीच था। अगर 2017 की बात की जाए तो इस साल यह 130 से 190 के बीच था, जबकि 2018 और 2019 में यह 100 से 180 के बीच था।

दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में सुधार एक सुखद एहसास है। जिसके लिए सालों से तमाम स्तरों पर प्रयास हो रहे थे, उसे लॉकडाउन ने 15 दिनों में ही हासिल कर लिया है। जरूरत इस स्थिति को आगे बनाए रखने की है।

-डा. दीपांकर साहा, सलाहकार, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

न्यूज गैलरी

राजधानी में अप्रैल में त्योहारों के आयोजनों पर रोक

नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। अब अप्रैल में पड़ने वाले त्योहार पर भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारियों व जिला पुलिस उपायुक्त को अपने-अपने इलाके में इस आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव को ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल भी पूजा के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह धार्मिक आयोजन अपवाद स्वरूप भी आयोजित करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे कड़ाई से लागू करे। अप्रैल में वैशाखी का त्योहार है। (जासं)

एरोसिटी में क्वारंटाइन अनिवासी भारतीय भेजे गए घर

नई दिल्ली: क्वारंटाइन के तहत 14 दिन की अवधि पूरा करने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आइजीआइ) के पास एरोसिटी के पांच होटलों में रह रहे कई लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। शुक्रवार को यहां पर क्वारंटाइन के तहत रखे गए शेष लोगों को भी सामान्य समारोह का आयोजन कर घर भेजा गया। आइजीआइ एयरपोर्ट पर उतरे 603 लोगों को यहां के होटलों में क्वारंटाइन किया गया था। दैनिक जागरण से बातचीत में लेमन ट्री होटल के संचालक पाटू केसवानी ने कहा कि अब तक उन्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा। जो भी हो विदेश से जब भारतीय स्वदेश आएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन में रखने की जरूरत होगी। इसके लिए होटल संचालक पूरी तरह तैयार हैं। (जासं)

सात हजार से अधिक मजदूरों के खातों में पहुंचे 5-5 हजार

नई दिल्ली : दिल्ली में लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे निर्माण कार्य से जुड़े 7,242 दिहाड़ी मजदूरों के खातों में गुरुवार को दिल्ली सरकार ने पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि भेज दी है। इनके खाते में दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 3.62 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी है। एक सप्ताह पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर बोर्ड ने पंजीकृत 32,358 निर्माण मजदूरों के खाते में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि भेजी थी। (जासं)

काबू में नहीं कोरोना, बढ़ सकता है लॉकडाउन

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

लॉकडाउन की अवधि कुछ ही दिन में पूरी होने वाली है। अब तक कोरोना काबू में नहीं आया है। दिल्ली में तो लॉकडाउन के दौरान ही संक्रमण तेजी से बढ़ा, जिसमें तब्लीगी जमात की बड़ी भूमिका रही। हालांकि अब अस्पतालों व सोसायटी में मरीज मिल रहे हैं। इस वजह से कोरोना के इलाज की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित डॉक्टरों की टीम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में दिल्ली में दो से तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ना तय है।

पांच सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के अध्यक्ष और यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि अभी कोरोना के कंटेनमेंट इलाके बढ़ रहे हैं। पहले तीन इलाके ऐसे थे, जहां संक्रमण अधिक था। सबसे पहले दिलशाद गार्डन में संक्रमण अधिक देखा गया। इसके बाद निजामुद्दीन का तब्लीगी मरकज बड़ा स्पॉट बना। मौजूदा समय में करीब दो दर्जन इलाकों में कंटेनमेंट लागू कर सील किया गया है।

आने वाले दिनों में ऐसे इलाके और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि पांच से सात दिन में समुदाय में संक्रमण फैलने का डर है। साथ ही कंटेनमेंट घोषित इलाके के सभी लोगों की स्क्रीनिंग जरूरी है। अगले एक-दो दिन में रैपिड टेस्ट की किट उपलब्ध हो जाएगी। कंटेनमेंट घोषित इलाकों को भी छोटे-छोटे क्लस्टर में बांटकर आसपास के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए क्योंकि संक्रमण बढ़ने की पूरी आशंका है।

गंगाराम अस्पताल के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. बॉबी भलोत्रा ने कहा कि यदि 14 अप्रैल के बाद एक-दो दिन लॉकडाउन से छूट भी दी गई तो यहां लोगों में इतना अनुशासन नहीं है कि वे शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर सकें। इससे भीड़ बढ़ सकती है। इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए।

वीटीएम की है कमी, रैपिड टेस्ट से जांच होगी आसान : डॉ. एसके सरीन ने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच के लिए मरीज के नाक से स्वैब लेना पडता है। स्वैब को लैब में ले जाने के लिए वायरल टेस्ट मीडिया (वीटीएम) की जरूरत पड़ती है। इसकी कमी है। यह आसानी से मिल नहीं रही है। रैपिड जांच के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड सैंपल से आसानी से जांच हो जाएगी। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोबारा आरटी-पीसीआर जांच भी आवश्यक होगी।

उन्होंने कहा कि चीन, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में इसका इस्तेमाल किया गया। संक्रमण के सात और 15 दिन बाद तक भी जांच कर सकते हैं। इसमें आइजीएम और आइजीजी दो तरह की जांच होती है। आइजीएम जांच से यह पता चलता है कि संक्रमण अभी हाल ही में हुआ है। आइजीजी में एंटीबॉडी की जांच होती है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति में आइजीएम नेगेटिव आने के बाद यदि आइजीजी एंटीबॉडी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होगा कि पीड़ित व्यक्ति में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो चुकी है।

दूसरे सप्ताह में आए अधिक मामले

दिल्ली में 29 मार्च तक स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में थी। तब तक सिर्फ 72 मामले आए थे। इसमें लॉकडाउन के पहले सप्ताह में 42 नए मामले जुड़े थे, लेकिन 30 मार्च से तब दिल्ली में परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई, जब तब्लीगी जमात का मामला सामने आया। इस वजह से लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में 431 नए मामले आए, जिसमें 320 तब्लीगी जमात के लोग थे। तीसरे सप्ताह में अब तक 217 नए मामले जुड़े, जिसमें 130 जमाती हैं। नौ अप्रैल तक दिल्ली में कुल 720 मामले मिल चुके हैं, जिसमें 430 जमाती व 290 अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा पहले कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आने वाले मरीज कम थे, ऐसे मरीजों की संख्या भी अप्रैल में बढ़ती दिखी। यह बात संक्रमण फैलने का संकेत दे रही है।

ट्रायल रहा सफल, ड्रोन से भी की जा सकेगी थर्मल स्कैनिंग

निहाल सिंह, नई दिल्ली

ड्रोन से सैनिटाइजेशन का ट्रायल सफल होने के बाद उत्तरी निगम ने अब ड्रोन से थर्मल स्कैनिंग का ट्रायल किया है। इसके माध्यम से न केवल मानव रहित थर्मल स्कैनिंग की जा सकती है, बल्कि सील किए गए इलाकों में कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा। यह ड्रोन 30 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके अलावा उस घर का सैनिटाइजेशन भी करेगा, जहां कोरोना संदिग्ध पाए जाएंगे।

उत्तरी निगम ने मजनूं का टीला की मार्केट में महापौर अवतार सिंह की उपस्थिति में इसका ट्रायल किया। वहां मौजूद लोगों की हवा से ही थर्मल स्कैनिंग की गई। हालांकि, इस दौरान किसी में भी लक्षण नहीं पाए गए। महापौर ने बताया कि इस तकनीक का उपयोग करके न केवल हम मेडिकल स्टॉफ की सुरक्षा सुनिश्चत कर सकेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सकेगी। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। शनिवार को सील की गई तिब्बती कॉलोनी में इसका ट्रायल किया जाएगा। इससे संकरी गलियों में बालकनी और घरों की छतों पर बैठे या खड़े लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा सकेगी। महापौर ने कहा कि जिस इलाके में कोरोना के मामले आते हैं, वहां पर डोर-टू-डोर सर्वे होता है। ऐसे में कर्मचारियों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। उनकी कोशिश हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जहां ड्रोन से हर घर में व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो जाए।

ऐसे करता है काम : ड्रोन बनाने वाली कंपनी इंडियन रोबोटिक सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक प्रशांत ने बताया कि इस ड्रोन में थर्मल स्कैनिंग के उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण ड्रोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से संचालित किए जाते हैं। इससे एक लेजर लाइट निकलती है, जिसके शरीर पर पड़ते ही सिस्टम की स्क्रीन पर व्यक्ति के शरीर का तापमान आ जाता है। यह मशीन सात सेकेंड में व्यक्ति की स्कैनिंग कर सकती है। इसमें लाउडस्पीकर भी लगा है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो उसके कपड़ों के रंग के जरिये पहचान करके बुलाया जा सकता है। यही नहीं इसमें लगे एचडी कैमरे से संदिग्ध की फोटो भी ली जा सकेगी।

मोबाइल ने खोला भेद, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर केस

जासं, नई दिल्ली : घर में क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए इसका उल्लंघन करना आसान नहीं है। इन पर पुलिस टेक्नीकल सर्विलांस से नजर रख रही है। क्वारंटाइन से बाहर निकलने पर मोबाइल के जरिये सीधे संदेश पुलिस तक पहुंच रहा है। ऐसा ही एक मामला फर्श बाजार इलाके में सामने आया है। यहां घर में क्वारंटाइन युवक बाहर निकल गया। मोबाइल का लोकेशन बदला तो पुलिस को अलर्ट मिल गया। पता चला कि वह घर से 344 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने अभिनव अग्रवाल नामक इस युवक के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया।

अभिनव अग्रवाल अनुपम अपार्टमेंट, फर्श बाजार में रहता है। अभिनव को 31 मार्च से घर में क्वारंटाइन किया गया था। गुरुवार शाम 6:50 बजे अभिनव अपने घर से बाहर निकला, तभी पुलिस को गूगल लाइव लोकेशन के जरिये अलर्ट मिला। उनकी लोकेशन की जांच की तो पता चला कि वह अपने घर से करीब 344 मीटर दूर है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।

मास्क न पहनने पर 137 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

घरों से जरूरी काम के सिलसिले में बाहर निकलने वाले ऐसे 137 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किए जाने के बाद भी इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य कार्य और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा मूवमेंट पास लेकर निकलने वाले लोगों को ही सड़क पर निकलने की अनुमति है। इन सभी लोगों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य है। जांच में शुक्रवार को ऐसे 137 लोग पाए गए, जो घर से बिना मास्क लगाए निकले। इन सभी लोगों के खिलाफ धारा-188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सबसे अधिक 32 मामले उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। 14 मामले शहादरा और बाहरी दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। 23 मामले दक्षिणी दिल्ली और 20 मामले उत्तरी दिल्ली में दर्ज किए गए। इसके अलावा शब-ए-बारात के दौरान सड़क पर निकलने के मामले में सिर्फ एक मामला महरौली थाने में दर्ज किया गया।

पुलिस ने हेल्पलाइन से दी 857 लोगों को मदद

जासं, नई दिल्ली : लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती करने के साथ दिल्ली पुलिस ने बुधवार को विभिन्न जिलों में ढाई लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। इसके लिए 15 जिलों में 400 एनजीओ का सहयोग लिया जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन पर 857 कॉल आई। इनमें से पैसे और खाना न होने से संबंधित सिर्फ तीन कॉल आई। इन परिवारों को एनजीओ की मदद से राशन उपलब्ध कराया गया है। 25 कॉल स्वास्थ्य सेवा के संबंध में थी और 567 कॉल मूवमेंट पास से संबंधित थी। हेल्पलाइन में 49 कॉल दिल्ली के बाहर से आई, जिन्हें संबंधित राज्यों की हेल्पलाइन नंबरों पर डायवर्ट किया गया। इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में सड़क पर रहने वाले, रिक्शा चालक, कबाड़ बीनने वाले और बेघर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 15 जिलों में 250 केंद्र बनाए हैं, जहां दोपहर और रात का भोजन लोगों को बांटा जा रहा है। लोगों को भोजन दिए जाने के दौरान शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। राजधानी के 15 जिलों में शुक्रवार को करीब दो लाख 60 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं कुछ एनजीओ व कंपनियों की मदद से जरूरतमंद लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे लोग घरों में रहें और कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने से बच सकें।

लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर 155 मामले दर्ज

जासं, नई दिल्ली : लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 155 एफआइआर दर्ज कीं। 3545 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये वे लोग थे, जो बिना कारण घर से बाहर सड़कों पर निकल आए थे। पुलिस पूछताछ में इनके पास घर से बाहर निकलने का कोई सही कारण नहीं मिलने पर इन्हें हिरासत में लिया गया। बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों में से 381 के वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया। इन लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। पुलिस की तरफ से 595 मूवमेंट पास ऑनलाइन जारी किए गए। इन लोगों को मूवमेंट पास आवश्यक कार्य के लिए जारी किए गए।

कवायद

डीयू में नए सत्र के लिए दाखिले की तैयारी शुरू

दाखिले से जुड़ी सूचनाओं के लिए कॉलेज प्राचार्यों को डीन एडमिशन ने लिखा पत्र, सभी कॉलेजों के दाखिले से जुड़ी जानकारी 30 अप्रैल तक भेजने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की तरफ से अकादमिक सत्र 2020-21 के दाखिले की तैयारी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय की डीन (एडमिशन) प्रो. शोभा बागई ने गुरुवार को डीयू के सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को अपने कॉलेजों के दाखिले से जुड़ी जरूरी सूचनाओं को डीयू की प्रवेश शाखा को 30 अप्रैल तक ईमेल के जरिये भेजने के लिए कहा है।

प्रो. शोभा बागई ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना के कारण लॉकडाउन किया गया। ऐसे में हमें आने वाले समय में नए अकादमिक सत्र के दाखिले की प्रक्रिया के सिलसिले में कम समय मिल सकता है। इसलिए पहले से ही इस मामले में तैयारी पूरी करके रखें। स्थिति सामान्य होते ही दाखिले की प्रकिया को लागू किया जाए।

ये जानकारी कॉलेजों को देने का निर्देश : दाखिले से जुड़ी सभी प्रकार की सूचनाओं को अपने कॉलेज की वेबसाइट में जारी करें, जिससे इन्हें डीयू में दाखिले की सूचना बुलेटिन में शामिल किया जा सके।

कॉलेज अपनी एडमिशन टीम का गठन करें और उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी प्रवेश शाखा को उपलब्ध कराएं। कौन से पाठ्यक्रम कॉलेज द्वारा पढ़ाए जाते हैं।

ऐसे स्वयंसेवकों व शिक्षकों की सूची तैयार करें जिनके मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी पर छात्र दाखिले से जुड़े सवाल पूछ सकें और वे उनके जवाब दे सकें।

पिछले साल लागू हुए कानून दस फीसद आर्थिक आरक्षण के तहत कुल 25 फीसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को सीटें मिलेंगी। डीयू ने इसे दो चरणों में बांटा था। पिछले वर्ष दस फीसद ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सीटों में दाखिले किए गए थे। अब इस वर्ष बचे हुई 15 फीसद ईडब्लूएस श्रेणी की सीटों में दाखिला किया जाएगा। कॉलेजों से कहा गया है कि वह अपने कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम की ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सूची भी तैयार करके डीयू की प्रवेश शाखा को दें।

दाखिले से जुड़ी सूचनाएं 30 अप्रैल तक ईमेल के जरिये भेजने को कहा। (फाइल)

जरूरी दस्तावेज की जांच सत्र शुरू होने के बाद की जाएगी

दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन (एडमिशन) प्रो. शोभा ने बताया है कि इस बार यह तैयारी की जा रही है कि नए सत्र में कक्षा शुरू होने के बाद ही छात्रों के जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पहले छात्र जब कटऑफ आने के बाद अपना दाखिला सुनिश्चित करवा लेते थे तो उसके बाद कक्षा शुरू होने से पहले उनके दस्तावेज की जांच की जाती थी।

एनडीएमसी ने बंगला पेस्ट्री शॉप से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बंगाली मार्केट की बंगला पेस्ट्री शॉप में स्वास्थ्य लाइसेंस के उल्लंघन पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने दुकान नंबर 34 से 37 तक के हेल्थ लाइसेंस लेने वाले बृजेश अग्रवाल के नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस में एनडीएमसी ने कहा है कि दुकान नंबर 34 से 37 में न केवल एनडीएमसी द्वारा हेल्थ लाइसेंस का उल्लंघन किया गया, बल्कि दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालने का कार्य किया गया है।

एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 339 के तहत नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब मांगा है। जवाब न देने की स्थिति में एनडीएमसी ने दुकान की सीलिंग की चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो एनडीएमसी इसी तरह से अन्य पर भी कठोर कार्रवाई करेगी।

बंगाली मार्केट में तीन लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी और एनडीएमसी की टीम ने जांच के दौरान बंगला पेस्ट्री शॉप की छत पर 35 लोगों को बुरी स्थिति में पाया था। यहां पर न केवल गंदगी थी, बल्कि बहुत छोटी जगह में रह रहे मजदूर शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 188व 269 में पेस्ट्री शॉप के संचालक ब्रजेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने बंगाली मार्केट के साथ, बाबर लेन, टोडरमल लेन, स्कूल लेन को सील कर दिया है।

8,800 से अधिक 'डिगिनिटी किट' वितरित कर चुका है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) घर से बाहर फंसे और जरूरतमंद लोगों को। इस किट में इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रसाधन सामग्री, एक-एक जोड़ी कपड़े और साफ-सफाई के सामान शामिल है।

डीएचएफएल के प्रमोटर वधावन को रियायत देकर फंसी उद्धव सरकार

घमासान ▸ लॉकडाउन में यात्रा की इजाजत देने वाला अफसर छुट्टी पर भेजा गया

भाजपा ने पूछा किसकी शह पर दिया गया 'वीवीआइपी ट्रीटमेंट'

राज्य ब्यूरो, मुंबई

पहले से ही कई मामलों में जांच एजेंसियों के निशाने पर चल रहे दीवान हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (डीएचएफएल) के संस्थापक वधावन खुद तो एक नई मुसीबत में फंसे ही, उनके कारण समूची उद्धव सरकार भी संकट में फंस गई है। लॉकडाउन के दौरान नियमों को ताख पर रख वधावन के परिवार और मित्र मंडली को पांच गाड़ियों से खंडाला से महाबलेश्वर जाने की छूट देने का मामला गले की हड्डी बन गया है। हमलावर भाजपा ने न केवल सवालों की झड़ी लगा दी बल्कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा भी मांग लिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सवाल किया है कि गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता ने सरकार में किसके आदेश पर वधावन परिवार को लॉकडाउन के दौरान खंडाला से महाबलेश्वर जाने की अनुमति दी।

इस बीच डीएचएफएल के संस्थापक कपिल एवं धीरज वधावन के विरुद्ध देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के

अमिताभ गुप्ता की फाइल फोटो। एएफपी

लिए आपदा प्रबंधन कानून एवं आइपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके उनके साथ महाबलेश्वर गए 23 लोगों के पूरे समूह को पंचगनी स्थित सेंट जेवियर्स हाईस्कूल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं उन्हें महाबलेश्वर जाने की अनुमति देनेवाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता को राज्य सरकार ने अवकाश पर भेज दिया है। लेकिन इतनी कार्रवाई पर ही उद्धव सरकार की मुसीबत टलती नजर नहीं आ रही है।

अमिताभ गुप्ता के पत्र ने भाजपा को उद्धव सरकार पर हमला बोलने का मौका उपलब्ध करा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं अब नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने सीधा सवाल किया है कि जब लॉकडाउन के दौरान पूरा देश घरों में है, तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी कैसे किसी को इस तरह की अनुमति प्रदान कर सकता है? ये अनुमति सरकार में किसकी शह पर दी गई? जबकि कई केंद्रीय जांच एजेंसियां पहले से कई मामलों में वधावन बंधुओं की जांच कर रही हैं। फड़नवीस ने मांग की है कि इस मामले की किसी केंद्रीय या निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए।

इससे पहले इस मामले को उठानेवाले भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भी वधावन बंधुओं को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वधावन बंधुओं के एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मधुर संबंध है।

उनका मानना है कि प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता को छुट्टी पर भेजना आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसके लिए गृहमंत्री अनिल देशमुख को त्यागपत्र देना चाहिए, साथ ही देशमुख को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर अमिताभ गुप्ता को ऐसा करने के लिए कहा। किरीट सोमैया ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भी पत्र लिखकर अमिताभ गुप्ता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि एफआइआर दर्ज अमिताभ गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने मुलुंड थाने में अर्जी दी है।

बता दें कि बुधवार को पहले से कई मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर चल रहे डीएचएफएल के वधावन बंधुओं को महाराष्ट्र गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) ने अपना करीबी बताते हुए पांच कारों में कुल 21 अन्य लोगों के साथ खंडाला से महाबलेश्वर जाने की अनुमति प्रदान करते हुए एक पत्र लिखा था। अब यही पत्र स्वयं अमिताभ गुप्ता एवं सरकार के गले की हड्डी बन गया है।

'तब्लीगी जमात वालों पर कार्रवाई से हिचक रही महाराष्ट्र सरकार' : देवेंद्र फड़नवीस ने गृहमंत्री अनिल देशमुख एवं राज्य सरकार पर तब्लीगी जमात के लोगों के संबंध में दी जा रही गलत जानकारी पर भी सवाल उठाया है। फड़नवीस ने कहा है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली से लौटे तब्लीगी जमात के सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। उसके बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि अभी 58 लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर मुंबई महानगरपालिका के आग्रह पर मुंबई पुलिस ने 150 जमातियों के गायब होने की एफआईआर दर्ज की। और अब गृहमंत्री देशमुख कह रहे हैं कि जमातियों के टेलीफोन बंद आने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।

जहां अन्य राज्यों में सामने न आनेवाले तब्लीगियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में उनके प्रति इस प्रकार का रवैया संदेह पैदा करता है। महाराष्ट्र उनपर कड़ी कार्रवाई करने से बच रहा है, तो कोई तो कारण होगा। जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है।

बिना अनुमति वधावन बंधुओं को क्वारंटाइन से न छोड़ें : सीबीआइ

▸ लंबे समय से सीबीआइ और ईडी को थी दोनों की तलाश, वाहन जब्त

▸ दोनों के खिलाफ हजारों करोड़ की हेराफेरी की चल रही जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : लॉकडाउन में नियमों को धता बताकर परिवार समेत खंडाला से महाबलेश्वर जाने वाले वधावन बंधुओं पर सीबीआइ ने भी नजर टेढ़ी कर दी है। सतारा के डीएम को पत्र भेजकर सीबीआइ ने कहा कि हिरासत में लेकर क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए वधावन बंधुओं को बगैर उसकी अनुमति के न छोड़ा जाए। उधर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शिकंजा कसते हुए वधावन बंधुओं के उन पांचों लग्जरी वाहनों को जब्त कर लिया जिनसे उनकी मित्र मंडली पिकनिक मनाने गई थी।

उल्लेखनीय है डीएचएफएल प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन कई और मामलों के साथ यस बैंस घोटाले में राणा कपूर की करोड़ों की रकम की हेरफेर में सीबीआइ जांच का सामना कर रहे हैं।

सीबीआइ अधिकारियों ने बताया कि की यस बैंक मामले में बीती 7 मार्च को मामला दर्ज होने के बाद से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ सीबीआइ ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर लिए हैं। सीबीआई को गुरुवार को जानकारी हुई ये दोनों सतारा जिले के पंचगनी में एक क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए हैं। इस पर जांच एजेंसी ने वहां के डीएम को ईमेल भेजकर दोनों को बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) न छोड़ें।

उल्लेखनीय है वधावन वंधुओं को अपने स्वजन के साथ लाकडाउन तोड़ने के आरोप में गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया था। उनको पांच कारों से सफर करने के लिए महाराष्ट्र के विशेष प्रमुख सचिव अमिताभ गुप्ता ने अनुमति दी थी। वधावन वंधुओं के फार्महाउस से पुलिस ने कुल 23 लोगों को पकड़ा था।

उल्लेखनीय है सीबीआइ ने 9 मार्च को इनके घर पर छापा मारा था। न मिलने पर उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआइ के आफिस बुलाया गया। वहां उपस्थित न आने पर 17 मार्च को कपिल व धीरज के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए। इसके बावजूद ये लोग सीबीआइ के सामने नहीं आए। सीबीआइ ने कहा कि यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर ने करीब 600 करोड़ का अनुचित लाभ लेकर डीएचएफएल में लगभग 3700 करोड़ का निवेश किया। डीएचएफएल पर मुखौटा कंपनियों के जरिये अपने 97,000 करोड़ के कुल लोन में से 31,000 करोड़ विदेश भेजने का भी आरोप है।

ईडी ने जब्त किए पांचों लग्जरी वाहन : प्रवर्तन निदेशालय ने वधावन के उन पांच वाहनों को जब्त किर लिया है जिनसे वे और मित्र मंडली खंडाला से महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गए थे। इनमें दो लैंडरोवर और तीन टोयटा फार्च्यूनर हैं। दो गाड़ियों पर झारखंड की नंबर प्लेट है जबकि तीन पर महाराष्ट्र का नंबर है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए सतारा के पुलिस अधीक्षक को एजेंसी ने पीएमएलए (प्रेंवेंशन आफ मानी लांड्रिंग एक्ट) के तहत पत्र भेजा था। जानकारी के मुताबिक ये वाहन कपिल वधावन के स्वामित्व वाली कंपनी आरकेडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी मैनेजमेंट लिमिटेड व गोल्डन बीच इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं। जांच अधिकारी ने सतारा पुलिस को हिदायत दी है कि वह जब्त करने का नोटिस वधावन बंधुओं को दे, एक प्रति वाहनों पर चस्पा करे और चाबियां अपने कब्जे में ले ले।

गौरतलब है कि और धीरज बधावन लंबे समय से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहे थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी दोनों जांच एजेंसियों के सामने पूछताछ के लिए नहीं आ रहे थे। इसी बीच ईडी को सूत्रों से जानकारी मिली कि ये दोनों महाबलेश्वर स्थित दीवान फार्म हाउस पर अपने करीबियों के साथ मौजूद हैं। ईडी ने सतारा पुलिस को मेल भेजकर इन्हें हिरासत में लेने को कहा। इस के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर क्वारंटाइन केंद्र में रख दिया।

नौसेना प्रमुख ने कहा, सामरिक साजो-सामान को कोरोना से बचाने की जरूरत

नई दिल्ली, प्रेट्र : नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने अपने जवानों से कहा है कि जिस तरह कोरोना वायरस दुनियाभर में फैल रहा है, उसे देखते हुए जहाजों और पनडुब्बियों जैसे महत्वपूर्ण सामरिक साजो-सामान को वायरस से मुक्त रखें। इसके अलावा करमबीर सिंह ने सशस्त्र बल को हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य देशों की सहायता के लिए तैयार रहने को भी कहा है।

▸ सशस्त्र बल को हिंद महासागर क्षेत्र में अन्य देशों की सहायता के लिए तैयार रहने को भी कहा

▸ महामारी से लड़ने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता

▸ जहाज और पनडुब्बियों पर काम करने वालों से हर वक्त मास्क पहनने का अनुरोध किया

करमबीर सिंह। फाइल

उन्होंने नौसेना के सभी कर्मियों को एक वीडियो संदेश में कहा कि कोरोना वायरस महामारी अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। इसका प्रभाव भारत सहित दुनियाभर में असाधारण रहा है। इस बीमारी से उत्पन्न खतरा वास्तविक, आसन्न और अभूतपूर्व है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन के तहत है।

एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है कि हमारे कर्मचारी और उनके परिवार सुरक्षित रहें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी परिचालन संपत्ति विशेषकर जहाज और पनडुब्बियां वायरस से मुक्त रहें। उन्होंने कहा कि जहाजों और पनडुब्बियों पर काम करने वालों के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे हर समय अपने मास्क पहनने का अनुरोध करूंगा।

एडमिरल सिंह ने वायरस से निपटने के लिए नौसेना द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया, जैसे कि भर्ती को रोकना, स्थानांतरण और नाविकों व अधिकारियों की आवाजाही पर रोक लगाना और प्रशिक्षण सेट अप को बदलना। उन्होंने कहा कि इन कदमों से काफी हद तक वायरस फैलने की आशंका को कम किया जा सका है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि यह मुश्किल समय है। आप में से कई लोग अपने परिवारों से अलग हो गए हैं। कुछ कर्मियों के माता-पिता गांवों में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन, मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे कर्मियों और हमारे समुदाय ने इस अवसर पर तेजी से काम किया है। हमारे जहाज और विमान सरकार और नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए स्टैंडबाय पर हैं। हम न केवल अपने देश, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों और अपने देश के द्वीपीय क्षेत्रों की मदद के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में हर नौसैनिक अपने साथियों की मदद के लिए तैयार है।

15 से मनरेगा कार्य शुरू करने को तैयार रहें राज्य : कृषि मंत्री

नई दिल्ली, आइएएनएस : देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बरकरार रखने के संबंध में जारी अटकलों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को सभी राज्यों से कहा है कि अगर स्थितियां इजाजत देंगी तो वे 15 अप्रैल से मनरेगा कार्य को जारी रखने के लिए तैयार रहें।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत में तोमर ने कहा, 'सभी राज्यों को कार्ययोजना तैयार रखने के लिए कहा गया है, ताकि स्थितियां इजाजत देती हैं तो मनरेगा का काम 15 अप्रैल से फिर से शुरू किया जा सके।' उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के कारण फलों और फूलों की खेती को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, इसका आकलन राज्य सरकारें ही कर सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का फसलों की कटाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फसलों की कटाई और बोआई के मौसम को देखते हुए केंद्र ने कृषि कार्य के लिए लॉकडाउन से छूट दे रखी है। मंडी, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानों को खोलने की छूट है। इसके बावजूद लॉकडाउन से कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गेहूं खरीद में देरी हुई है।

अखबारों पर पाबंदी की मांग मौलिक अधिकारों का हनन : मद्रास हाई कोर्ट

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लॉकडाउन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जीवंत मीडिया की बहुत अहमियत है।

▸ अखबारों से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के तर्कों में कोई दम नहीं

▸ समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका खारिज

प्रतीकात्मक फोटो

समाचार पत्रों के प्रकाशन पर यदि रोक लगाई जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत न केवल प्रकाशक और संपादक, बल्कि पाठक के भी मौलिक अधिकारों के हनन के समान होगा
– मद्रास हाई कोर्ट

याचिकाकर्ता के इस तर्क कि समाचार पत्रों से कोरोना वायरस फैल सकता है लिहाजा इनका प्रकाशन रोक दिया जाए, को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मात्र आशंका के आधार ऐसा नहीं किया जा सकता। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन. किरुबाकरन और जस्टिस आर. हेमलता की पीठ ने कहा कि अगर समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाई जाती है तो यह प्रकाशकों, संपादकों और पाठकों के भी मौलिक अधिकारों के हनन के समान होगा। पीठ ने कहा कि एक जीवंत मीडिया भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश की थाती है। अतीत में आजादी की लड़ाई के दौरान इसी मीडिया ने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आपातकाल के काले दौर में भी इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही।

प्रिंट मीडिया न केवल लोगों के विचारों को परिलक्षित करता है, बल्कि सरकारों की निगरानी करता है। यह उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी को भी उजागर करता है।

पीठ ने इस संबंध में 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन बनाम केंद्र सरकार के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया। तमिलनाडु सरकार के महाधिवक्ता पीएच अरविंद पांडियन के तर्कों से सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि रिकार्ड व मीडिया रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह तर्क कतई सही नहीं है कि समाचार पत्रों के माध्यम से या कागज की सतह से कोरोना बहुत व्यापक तरीके से फैल रहा है। इस विषय में अभी बहुत सीमित शोध हुआ है। केवल आशंका या मामूली संभावना के आधार पर समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगाना उचित नहीं है।

सोनिया ने कोरोना के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति बनाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने कोरोना के खिलाफ एक्शन की रणनीति बनाई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में वह अपने काडर और संगठन का इस्तेमाल करके युद्ध स्तर पर कोरोना टेस्ट के लिए तैयार करेंगे।

सोनिया गांधी ने शुक्रवार को देश में कोरोना के परीक्षण केंद्रों की कमी पर चिंता जताते हुए एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक वित्तीय पैकेज की मांग की। साथ ही पार्टी के लोगों से किसानों की मदद करने की अपील की है।

सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से लंबी बातचीत की है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ अग्रिम मोर्चा लेने वाले कर्मचारियों को भी वित्तीय लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए।

मोदी ने नेपाल को हरसंभव मदद का दिया भरोसा

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के मुद्दे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ चर्चा की। उन्होंने ओली को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने इस विकट घड़ी में आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमति जताई।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात हुई। हमने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थितियों पर चर्चा की। मैं इस चुनौती से निपटने में नेपाल के लोगों की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। हम कोरोना वायरस के खिलाफ साझी लड़ाई में नेपाल के साथ एकजुट खड़े हैं।'

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस की महामारी, दोनों देशों के नागरिकों तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर ओली की तारीफ की। ओली ने भी पीएम मोदी की तरफ से कोरोना संकट के दौरान दक्षेस देशों में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई पहल की प्रशंसा की।'उधर, ओली ने भी मोदी के साथ हुई बातचीत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ट्वीट किया, 'मैं भारत सरकार को दवा समेत अन्य मदद के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने लॉकडाउन के कारण दोनों देशों में फंसे एक-दूसरे के नागरिकों का ध्यान रखने पर बल दिया है।' नेपाली विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दोनों देशों के नेताओं के बीच संवाद को सार्थक बताया।

पीएम मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन आदि से बात कर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने ओली से बातचीत की।

दिवालिया मामले में माल्या फिलहाल लंदन हाई कोर्ट से बच निकला

लंदन, प्रेट्र : भारतीय बैंकों से मोटा कर्ज लेकर भागा शराब कारोबारी विजय माल्या दिवालिया मामले में लंदन हाई कोर्ट से भी फिलहाल बच निकला है। हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ की याचिका पर फिलहाल सुनवाई टाल दी है। बैंकों ने माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की थी, ताकि वो उससे करीब नौ हजार करोड़ रुपये का अपना कर्ज वसूल सकें।

लंदन हाई कोर्ट के दिवाला विभाग के जस्टिस माइकल ब्रिग्स ने अपने फैसले में कहा कि माल्या को उसकी भारतीय सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला आने तक वक्त दिया जाना चाहिए। माल्या ने याचिका में भारतीय बैंकों के संपूर्ण कर्ज को चुकाने का प्रस्ताव दिया और अनुमति मांगी है।

गुरुवार को दिए आपने आदेश में जस्टिस ब्रिग्स ने कहा कि इस समय बैंकों द्वारा इस तरह की याचिका को आगे बढ़ाने का कोई स्पष्ट लाभ नहीं है।

ज्यादा कोरोना टेस्ट को लेकर प्रियंका ने योगी को लिखा पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ छह करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया का दिया उदाहरण

▸ राहुल गांधी ने स्वास्थ्यकर्मियों को उनके योगदान के लिए किया सैल्यूट

यूं तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) कोरोना टेस्टिंग की संख्या को लेकर संतुष्ट है लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इससे राजी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उन्होंने सूबे में कोरोना के टेस्ट और इलाज की सुविधा में तत्काल इजाफे का अनुरोध किया है। जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वास्थ्यकर्मियों, आशाकर्मियों आदि के प्रयासों की सराहना की है। राहुल ने इन योद्धाओं की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा है कि देश भी उनके इस योगदान के लिए आभारी रहेगा।

प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पत्र के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि सूबे में टेस्ट की संख्या बढ़ाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। छह करोड़ की आबादी वाले देश दक्षिण कोरिया में प्रति एक हजार लोगों में से छह व्यक्तियों का टेस्ट कर इस महामारी को काबू में करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक करीब सात हजार लोगों की ही सैंपलिंग हुई है। सूबे की जनसंख्या के हिसाब से यह अनुपात काफी कम है और इसलिए टेस्टिंग की गति बढ़ाना जरूरी है। प्रदेश के कई क्वारंटाइन सेंटरों से बदहाली की आ रही खबरों पर चिंता जताते हुए प्रियंका ने इन्हें दुरूस्त करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के इस बीमारी से लड़ने के सुझावों का हवाला भी दिया है कि सहभागी प्रशासन, सही जानकारियों के आधार पर अधिकतम जनसंवाद और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस चुनौती से निपटने में भागीदारी बेहद जरूरी है।

पूरे जीवन की कमाई दान करने वाली देवकी भंडारी को राष्ट्रपति ने सराहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अपने जीवन भर की जमा पूंजी दान करने वाली उत्तराखंड के चमोली की देवकी भंडारी के दान की तारीफ अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी की है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी इस कल्याणकारी भावना से पता चलता है कि कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए हमारे देशवासियों का संकल्प कितना मजबूत है।

चमोली के गोचर की रहने वाली देवकी भंडारी बुधवार को उस समय चर्चा में आईं, जब उन्होंने बैंक पहुंचकर वहां जमा अपनी कुल दस लाख रुपये की पूंजी कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में जमा करा दी। इस बीच शुक्रवार को जैसे ही देवकी भंडारी के दान की खबर राष्ट्रपति को लगी, तो उन्होंने ट्वीट कर उनके योगदान को सराहा और कहा कि उन्होंने एक सच्चे राष्ट्र निर्माता की भावना से अपनी जीवन भर की कमाई के दस लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में सौंप दिए। इससे पहले उनके इस दान की केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी तारीफ की थी।

पहल

लॉकडाउन हटने के बाद भी स्कूल और कॉलेजों के खुलने पर संशय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'पढ़े भारत ऑनलाइन' नाम से छेड़ी मुहिम

घर बैठे ही पढ़ाई को और बेहतर बनाने में जुटी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आने वाले दिनों में लॉकडाउन भले ही हट जाएगा, लेकिन जब तक कोरोना से बचाव का कोई कारगर उपाय सामने नहीं आ जाता, सरकार तब तक छात्रों को फिलहाल घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर जोर-शोर तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही 'पढ़े भारत ऑनलाइन' नाम से नई मुहिम भी शुरू की है। इसके तहत ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए देश भर के विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को इस मुहिम का एलान किया। साथ ही हफ्ते भर के भीतर सभी से ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने से जुड़े सुझाव देने को कहा है। उन्होंने इस दौरान ऐसे संस्थानों, विशेषज्ञों व छात्रों से अनिवार्य रूप से अपने सुझाव देने को कहा है, जो मौजूदा समय में ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं या उससे जुड़े हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही एक अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र से ही छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। जो टेलीविजन के साथ ऑनलाइन के दूसरे माध्यमों से छात्रों की दी जा रही है। इस दौरान जो बच्चे इस साल दसवीं और बारहवीं में हैं, उसके लिए लाइव क्लास भी लगाई जा रही है।

मंत्रालय से जुड़े अफसरों के मुताबिक ऑनलाइन शिक्षा को तेजी से बढ़ावा देने का यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उपजी परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि मौजूदा हालत में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी स्कूल- कॉलेजों में कोरोना के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कोशिश है कि जब तक देश कोरोना के संक्रमण के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो जाता है,तब स्कूल-कालेजों में पढ़ाई शुरू करना कठिन होगा। ऐसे में बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा ही दी जाएगी। यही वजह है कि देश भर से ऑनलाइन शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसे कैसे और रोचक बनाया जा सकता है आदि सवालों से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं। इनके आने के बाद इसमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों में मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के साथ परीक्षा कराने को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। स्थिति नहीं सुधरी, तो आने वाले दिनों में इसे भी आजमाया जा सकता है।

लॉकडाउन बढ़ाने और गर्मी की छुट्टियां निलंबित करने का आग्रह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दिनेश कुमार गोस्वामी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है जिसमें कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन को कम से कम 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने और देश की सभी शिक्षण संस्थाओं तथा सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों की गर्मी की छुट्टियां निलंबित किए जाने का आग्रह किया गया है।

पत्र में गोस्वामी ने कहा है कि कोरोना महामारी भारत सहित दुनिया के सभी बड़े देशों में फैली है। देश के अंदर भी संक्रमित और इससे होने वाली मौतों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन खत्म करना ठीक नहीं होगा।

पत्र में गोस्वामी ने कहा है कि कम से कम 30 अप्रैल तक तो लॉकडाउन जारी ही रहना चाहिए। हालांकि पत्र में यह भी कहा गया है कि इस दौरान बंदी रहने से देश भर की अदालतों में व अन्य जगह काम का बोझ काफी बढ़ जाएगा। ऐसे में देश भर के शिक्षण संस्थानों और सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों की गर्मी की छुट्टियां निलंबित कर दें।

कह के रहेंगे माधव जोशी

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर क्यों मचा है इतना हंगामा

मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। कारण यह कि इस दवा को कोरोना के भी इलाज में कारगर माना जाने लगा है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह दवा कोरोना वायरस का संक्रमण रोक सकती है या इस बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन महामारी से बढ़ते मौत के तांडव ने पूरी दुनिया को इस स्थिति में ला दिया है कि जहां कहीं भी थोड़ी-सी आशा की किरण दिखती है, हम उसकी संभावना तलाशने में लग जाते हैं। इस बेचैनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सलाह से इतर जाकर भी भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की न सिर्फ मांग की, बल्कि आपूर्ति नहीं होने पर प्रतिशोधी प्रतिक्रिया की चेतावनी तक दे डाली। हालांकि भारत ने भी इस दवा के निर्यात पर पहले प्रतिबंध लगाया और फिर बाद में मानवीय आधार पर उसमें कुछ ढील देने का एलान किया है। अब इन सवालों के जरिए जानते हैं, क्या है मामला।

क्या है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन?

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दशकों से मलेरिया के इलाज की एक निर्धारित दवा है। इसका इस्तेमाल रूमटॉइड आर्थ्राइटिस तथा ल्यूपस (त्वचा पर निकलने वाला एक क्रॉनिक तथा उभरा हुआ घाव) जैसे ऑटोइम्यून रोगों के इलाज के लिए भी होता है।

क्यों माना जाने लगा कोरोना का संभावित इलाज?

एक प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया कि क्लोरोक्विन कोरोना वायरस को कोशिकाओं पर हमले से रोकता है। हालांकि टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिसेस में जो दवा वायरस पर काबू पाते हैं, वैसा मानव शरीर में हमेशा नहीं होता है। साथ ही यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंफ्लूएंजा तथा अन्य वायरल रोगों को रोकने या उनके इलाज में सफल नहीं है। लेकिन चीन और फ्रांस के डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कभी-कभी एंटीबॉयोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ दिए जाने से रोगियों को राहत मिलती दिखती है। परंतु यह अध्ययन छोटे पैमाने पर हुआ। इसलिए व्यापक पैमाने पर यह पता नहीं चल पाया कि दवा ने काम किया या नहीं। फ्रांसीसी अध्ययन को इस आधार पर नकार दिया गया कि यह मानकों को पूरा करने वाला नहीं था।

और भी अध्ययन की जरूरत: दूसरी ओर, चीन के एक हालिया अध्ययन (जिसमें कंट्रोल ग्रुप को शामिल किया गया) से यह बात बताई गई कि कोरोना के हल्के मामले में रोगियों के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मदद मिल सकती है। लेकिन यह अध्ययन भी सीमित पैमाने पर हुआ, जिसमें कुल 62 रोगी ही थे और उन्हें अन्य दवाएं भी दी गईं। शोधकर्ता खुद भी कहते हैं कि इस संबंध में और भी अध्ययन की जरूरत है। कोरोना रोगियों में इम्यून सिस्टम काफी सक्रिय हो जाता है, जिससे सूजन/जलन पैदा होने के साथ ही फेफड़ा और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। जबकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अति सक्रिय इम्यून सिस्टम पर काबू पाने वाला माना जाता है। डॉक्टर उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस स्थिति को शांत करता है। लेकिन क्या यह वाकई काम करता है, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है।

क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन संक्रमण से बचा सकता है?

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकता है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के शोधकर्ता कोरोना के रोगियों के साथ रहने वाले लोगों पर इस दवा का असर परखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह उन्हें संक्रमण से बचा सकता है।

क्या एफडीए से यह दवा स्वीकृत है?

जहां तक अमेरिका का संबंध है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मलेरिया, रूमटॉइड आर्थ्राइटिस तथा ल्यूपस के इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दी है न कि कोविड-19 के लिए। लेकिन डॉक्टरों को इस बात की अनुमति है कि वे यदि सोचते हैं कि किसी स्थिति में यह मददगार हो सकता है तो इस दवा की सलाह दे सकते हैं। इसे ऑफ लेवल इस्तेमाल कहते हैं। मार्च के उत्तरार्द्ध में एफडीए ने अस्पतालों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ऐसे रोगियों के इलाज के लिए आपात अनुमति दी, जो क्लीनिकल ट्रायल के योग्य नहीं हैं। लेकिन इसके बारे में रोगी तथा परिवार को सूचना देनी होगी तथा रोगियों के स्वास्थ्य पर नजर भी रखनी होगी। लेकिन आपात अनुमति संघीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

क्या कोरोना रोगियों को दी जा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन?

कोरोना का अभी तक कोई सिद्ध उपचार नहीं होने से कई अस्पताल इस उम्मीद में रोगियों को यह दवा देने लगे हैं कि इससे मदद मिल सकती है। दुनिया भर में नियंत्रित समूह पर इस दवा का क्लीनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। अमेरिका में 2 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर इसका ट्रायल शुरू हुआ, जिसके लिए 44 मेडिकल सेंटरों पर 510 रोगियों का नाम दर्ज किया गया है। अध्ययन से पता चलेगा कि यह दवा कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है या नहीं। यदि इसे असरकारी नहीं पाया गया तो संसाधनों का इस्तेमाल अन्य संभावित इलाज खोजने में किया जाएगा।

क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से कोई खतरा है?

सभी दवाओं की तरह इसके भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह दिल, रेटिना संबंधी आंख की समस्या, लिवर और किडनी के रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा जी मिचलाना, डायरिया, मनोदशा में बदलाव तथा त्वचा पर चकते जैसे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ह्रदय रोग विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तथा एजिथ्रोमाइसिन दिल के काम में खतरनाक व्यवधान पैदा कर सकती हैं। कुल मिलाकर माना जाता है कि जिन लोगों में ऐसी बीमारियां नहीं हैं, उनके लिए अपेक्षाकृत यह सुरक्षित है। लेकिन यह पता नहीं है कि क्या कोविड-19 के गंभीर बीमारों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुरक्षित है या नहीं।

क्या कोरोना संक्रमण रोकने को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं?

बगैर डॉक्टर से पूछे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हों और उन्हें यह भी पता हो कि आप अभी कौन-सी दवा ले रहे हैं। ऐसे में अपने मन से यह दवा लेना नुकसानदेह हो सकता है।

(स्रोत : न्यूयार्क टाइम्स)

कोरोना एक नजर

घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के लिए वाट्सएप नंबर जारी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाओं के मामले की रिपोर्ट देने के लिए वाट्सएप नंबर जारी किया है। आयोग ने कहा है कि वाट्सएप नंबर 7217735372 पहले से ही संचालन में मौजूद ऑनलाइन शिकायत लिंक और ईमेल के अतिरिक्त है। यह आपात नंबर घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए है। (प्रेट्र)

बेसहारा विक्षिप्तों की व्यवस्था पर केंद्र से जानकारी मांगी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह में देश भर में सड़कों पर बेसहारा घूम रहे विक्षिप्तों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में सूचित करने को कहा है। एक बयान में आयोग ने कहा है कि उसने मानसिक रूप से बीमार लोगों के मानवाधिकार के उल्लंघन पर शिकायत को संज्ञान में लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को दो सप्ताह में जवाब सौंपने के लिए कहा है। (प्रेट्र)

स्पाइसजेट ने हो ची मिन्ह के लिए पहली मालवाहक सेवा दी

मुंबई : बजट कैरियर स्पाइसजेट ने शुक्रवार को वियतनाम के हो ची मिन्ह के लिए पहली बार मालवाहक सेवा के रूप में उड़ान भरी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हैदराबाद से विमान करीब 16 टन मेडिकल आपूर्ति लेकर रवाना हुआ। इसके अलावा इसका एक मालवाहक महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों को लेकर बेंगलुरु से सिंगापुर रवाना हुआ। (प्रेट्र)

नौ अप्रैल तक 180 विमानों ने 258.28 टन सामान ढोया

नई दिल्ली : 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू होने के दिन से लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत कुल 180 विमानों ने गुरुवार तक 258.24 टन सामान परिवहन किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने 14 अप्रैल तक जारी लॉकडाउन के दौरान हवाई मार्ग से आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ानें शुरू की थीं। (प्रेट्र)

कर्मचारी की मौत पर 50 लाख देगी राजस्थान सरकार

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मौत होने पर आश्रितों को 50 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत होने पर इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने स्वास्थ्यकर्मियों का 50 लाख रुपये का बीमा कराने की भी घोषणा की है। (जासं)

13 देशों को दी जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन

तैयारी ▶ जरूरत से तीन गुना रखकर बाकी का निर्यात करेगा भारत

निजी कंपनियों को नहीं सिर्फ विदेशी सरकारों को दी जाएगी दवा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोविड-19 में कारगर समझी जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) दवा की वैश्विक मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल भारत ने 13 देशों को इसकी आपूर्ति करने का फैसला किया है। इनमें अमेरिका, स्पेन और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही भारतीय कंपनियों के साथ इस दवा के लिए अनुबंध कर रखे थे। दूसरे देशों में अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश व मालदीव भी शामिल हैं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर उक्त दवा के अलावा पैरासीटामोल (पीसीएम) भी दी जाएगी। हिंद महासागर में स्थित दो अन्य छोटे देशों सेशल्स व मॉरीशस के अलावा ब्राजील, डोमिनिक रिपब्लिक व बहरीन को भी एचसीक्यू की आपूर्ति की जा रही है।

भारत इन दवाओं की आपूर्ति का फैसला दो तथ्यों के आधार पर ले रहा है। पहला यह कि घरेलू जरूरत पूरी होने के बाद ही यह दूसरे देशों को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भारत अभी एचसीक्यू की 20 करोड़ टैबलेट तैयार कर सकता है। लेकिन जरूरत अभी एक करोड़ की है जबकि 3.28 करोड़ टैबलेट तैयार हैं। मोटे तौर पर अभी योजना यह है कि जरूरत से तीन गुना ज्यादा टैबलेट अपने पास रखकर दूसरे देशों को मानवता के आधार पर इसकी आपूर्ति की जाए।

दूसरा तथ्य यह है कि भारत इन दवाओं का निर्यात निजी कंपनियों को नहीं करेगा बल्कि इसकी आपूर्ति सीधे विदेशी सरकारों को की जाएगी। विदेश मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में कई देशों की तरफ से इसकी मांग आई है और शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि कई देश आपातकालीन स्थिति के लिए जरूरत से ज्यादा इसकी मांग कर रहे हैं। हर देश की मांग की समीक्षा करने के बाद अपने स्टॉक के मुताबिक उनके बीच इन दवाओं का विभाजन होगा। अमेरिका, स्पेन जैसे देशों ने पहले ही भारतीय कंपनियों को इसके ऑर्डर दे रखे हैं इसलिए उन्हें पहले आपूर्ति की जाएगी। एक तरह से 'फर्स्ट कम, फर्स्ट गेट' (पहले आइए, पहले पाइए) का नियम लागू किया जाएगा। इस बारे में विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच गहन विमर्श से फैसला होगा। पहले चरण में उक्त 13 देशों को तकरीबन 1.5 करोड़ एचसीक्यू की टैबलेट्स दी जाएंगी। विदेश मंत्रालय से अनुमोदन पर ही निर्यात का फैसला होगा। वैसे भारत अगर दूसरे देशों को दवा की आपूर्ति कर रहा है तो वह दूसरी चिकित्सा सामग्री का आयात भी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ में तीन गुना बढ़ी इस दवा की मांग

नईदुनिया, रायपुर : कोरोना के फैलने के बाद विश्वभर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी मांग तीन गुना हो गई है। कुछ जिलों के सरकारी अस्पताल भी अब इस दवा की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कुछ जिला अस्पतालों में विकल्प के रूप में मौजूद अन्य सॉल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है।

थोक दवा व्यापारियों के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग इन दिनों तीन गुना तक बढ़ गई है। इसकी प्रमुख वजह यह भी बताई जा रही है कि इसकी सप्लाई सरकारी अस्पतालों में की जा रही है।

अभी दवा की कमी नहीं

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कारपोरेशन के संचालक भुवनेश यादव के अनुसार अभी 3.40 लाख दवाएं स्टॉक में हैं, जो छत्तीसगढ़ की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त हैं। अस्पतालों में मांग के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है। अभी कहीं कोई कमी नहीं है।

अमेरिका में पहले रेड अलर्ट खत्म कर चुकी है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन

प्रशांत कुमार, कन्नौज

कोरोना के इलाज के लिए इस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा खूब चर्चा में है। आज से 22 साल पहले भी इस दवा ने अमेरिका के एक अस्पताल का रेड अलर्ट खत्म किया था। तब यह दवा कन्नौज से अमेरिकी राज्य न्यूजर्सी के एक अस्पताल में भर्ती भारतवंशी लड़की के लिए गई थी।

कन्नौज के गांव अंदौआ निवासी डा. कमलेंद्र सिंह यादव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से फिजिक्स में पीएचडी के बाद क्वांटम माल्युकुलस की स्टडी और इंटर्नशिप के लिए न्यूजर्सी मेडिकल कालेज गए थे। वहां, उन्होंने डीएनए और बायो केमिस्ट्री में शोध किया, जिस पर लिखी किताबें न्यूजर्सी में पसंद की गईं। उन्हें वहीं नौकरी मिल गई तो 1998 में वह अपने परिवार को भी अमेरिका लेकर चले गए।

इस दौरान उनकी बड़ी बेटी को हल्का बुखार था, जिसे न्यूजर्सी के एक अस्पताल में भर्ती कर जांच कराई तो मलेरिया निकला। चूंकि अमेरिका में मलेरिया के केस नहीं होते थे, इसलिए वहां इसकी दवा भी नहीं मिलती थी।

इस पर डॉ. कमलेंद्र ने अपने शिक्षक पिता मिश्रीलाल यादव को फोन कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां मंगवाईं। कमलेंद्र के मित्र प्रवीन त्रिपाठी उक्त दवा को कन्नौज से दिल्ली ले गए और वहां से पार्सल कर अमेरिका भेजा। इस दवा के इस्तेमाल के बाद उनकी बेटी ठीक हो गई। इस बात से इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है।

22 साल पूर्व न्यूजर्सी के एक अस्पताल को भेजी गई थी मलेरिया की दवा

▶ जिला निवासी डॉ. कमलेंद्र ने मलेरिया पीड़ित बेटी के लिए था मंगवाया

मलेरिया का केस देख अस्पताल में था रेड अलर्ट

डॉ. कमलेंद्र वर्तमान में कोलंबिया स्थित मिसौरी विवि में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि जांच में जब बेटी को मलेरिया से पीड़ित पाया गया तो अस्पताल में रेड अलर्ट घोषित हो गया था। जहां, बेटी भर्ती थी वहां, लोग सतर्कता के साथ जाते थे।

टीबी की जांच करने वाली मशीन का उपयोग कोविड-19 के लिए होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की क्षमता बढ़ाने की कोशिशों के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने 'दवा-प्रतिरोधी (डी-आर) टीबी' की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नैदानिक मशीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है।

देश की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई आइसीएमआर ने शुक्रवार को कहा कि 'ट्रूलैबटीएम वर्कस्टेशन पर ट्रूनैलटीएम बीटा सीओवी जांच' को मान्यता दी है और उसने इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर सिफारिश की है। इस सिलसिले में एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए आइसीएमआर ने कहा कि गले या नाक का स्वाब किट के साथ उपलब्ध वायरस लायसिस बफर से 'वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम' (वीटीएम) में एकत्र किया जाएगा।

इसमें कहा गया है, 'पहले के अध्ययनों में यह प्रदर्शित हुआ है कि वायरस लाइसिस बफर ने निपाह और एच1एन1 वायरस को नियंत्रित किया है। वायरस लाइसिस बफर के जरिये सार्स-सीओवी-2 को निर्यंत्रित करने के बाद वायरस आरएनए की स्थिरता के नतीजों का आइसीएमआर-एनआइवी, पुणे से इंतजार है।'

दिशा-निर्देश में कहा गया है, 'तब तक ट्रूनैट बीटा जांच सभी जैव सुरक्षा एहतियातों के साथ ही प्रयोगशालाओं में बीएसएल 2 और बीएसएल 3 इकाइयों में की जानी चाहिए।'

बंगाल के किसानों को कुनैन की मांग बढ़ने की उम्मीद, इलाज में है प्रभावी

प्रेट्र, कोलकाता : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने के बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सिनकोना पेड़ों की बागवानी करने वाले किसानों को कुनैन की मांग बढ़ने की भी उम्मीद जगी है। दरअसल, मलेरिया के प्रभावी इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा कुनैन की गोलियों का उपयोग भी किया जाता है, जो सिनकोना पेड़ों की छाल से तैयार होती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 1862 में सिनकोना की बागवानी शुरू हुई और दशकों तक फूलती-फलती रही, क्योंकि देश में मलेरिया के मरीजों की संख्या में कुछ खास कमी नहीं आई। अब इस दवा की मांग भारत सहित दुनिया के कई देशों में है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में भारत की आधी आबादी को मलेरिया होने का खतरा था।

▶ मलेरिया के मरीजों के इलाज में होता है उपयोग, सिनकोना पेड़ों की छाल से की जाती है तैयार

▶ दार्जिलिंग में की जाती है सिनकोना की बागवानी

हाल के कुछ वर्षों में सिनकोना की बागवानी करने वाले किसानों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुनैन की गोलियों का सिंथेटिक तरीके से उत्पादन होने लगा। बंगाल में सिनकोना बागवानी के निदेशक सैम्यूएल राय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मलेरिया की दवाओं की मांग बढ़ी है और इससे दार्जिलिंग में सिनकोना की बागवानी करने वालों को उम्मीद जगी है। हमें आशा है कि व्यापार में सुधार आएगा। दवा बनाने वाली कंपनियां अब भी सिनकोना पेड़ों की छाल ई-नीलामी के जरिये खरीदतीं हैं, क्योंकि इसका उपयोग अन्य कई दवाओं के निर्माण में भी होता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही।

पेड़ों की छाल से होती है तैयार : हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि में राय ने कहा कि हाईड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक सिंथेटिक अणु है, जो क्लोरोक्विन से बनता है और यह रसायनिक तरीके से तैयार कुनैन है। उन्होंने बताया कि कुनैन की गोलियां सिनकोना पेड़ों की छाल से तैयार प्राकृतिक तत्व हैं।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मांगी जानकारी : यह पूछने पर कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यापार बेहतर होगा, राय ने कहा कि मलेरिया की दवाओं की बढ़ती मांग को देखकर ऐसा लगता है कि सिनकोना पेड़ों की छाल से कुनैन का प्राकृतिक उत्पादन बढ़ेगा। मलेरिया की दवाओं की मांग बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने हमसे सिनकोना पेड़ों की सूखी छाल के बारे में सूचना मांगी है। हमें आशा है कि प्राकृतिक कुनैन लाभकारी होगा। राय ने बताया कि सिनकोना की बागवानी बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में होती है।

महिलाओं ने संभाली गांव की जिम्मेदारी...

देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच जम्मू-कश्मीर में महिलाओं ने गांवों में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने का जिम्मा संभाल लिया है। जम्मू के छाठा गांव में महिलाओं ने शुक्रवार को बाहरी लोगों को लाठी लेकर रोका। प्रेट्र

लगाई अर्जी

कई लोगों में नजर नहीं आते बीमारी के लक्षण, ऐसे लोग हो सकते हैं कोरोना के वाहक, ऐसे में बड़े स्तर पर जरूरी है जांच

घर-घर कोरोना जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घर-घर जाकर जांच कराने की मांग की गई है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। इसकी शुरुआत उन शहरों और जगहों से होनी चाहिए जहां संक्रमण के हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा मांग है कि कोरोना से जंग के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष, पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में एकत्रित किया गया धन कोरोना से निपटने, सुरक्षा किट खरीदने और क्वारंटाइन सेंटर स्थापित करने आदि में खर्च किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि भारत में कोरोना संक्रमण की जांच दर दुनिया में सबसे कम है। पिछले कुछ दिनों में जितनी तेजी से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है वह चिंता की बात है। संक्रमण रोकने के लिए इसकी चेन तोड़ना जरूरी है। भारत का बुनियादी प्रयास इस संक्रमण को कम्यूनिटी संक्रमण बनने से रोकना है न कि बड़े पैमाने पर टेस्ट कर संक्रमण की पहचान कर उसे रोकना है जिसके लिए दूसरी तरह के प्रयासों की जरूरत है।

कहा गया है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण हों और वह कोरोना संक्रमित हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी में लक्षण तो कोरोना जैसे दिखें, लेकिन वह कोरोना संक्रमित न हो। इसके अलावा ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण हो, लेकिन उनमें इसके लक्षण न दिखाई दे रहे हों, ऐसे लोग कोरोना के वाहक हैं। इस सबकी पहचान बड़े पैमाने पर घर-घर जांच से ही हो सकती है।

यह जनहित याचिका इलाहाबाद के चार वकीलों शाश्वत आनंद, अंकुर आजाद, फैज अहमद और सागर की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार व डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पक्षकार बनाया गया है।

▶ हॉटस्पॉट शहरों और जगहों से हो इसकी शुरुआत

▶ भारत में कोरोना संक्रमण की जांच दर दुनिया में सबसे कम

▶ समय रहते जांच कर कम किया जा सकता है जोखिम

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

खाड़ी में फंसे प्रवासी कामगारों की मदद के लिए याचिका दायर

नई दिल्ली, (प्रेट्र) : सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में खाड़ी देशों में फंसे भारतीय कामगारों को बचाने और उन्हें वापस लाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। कोरोना महामारी के कारण प्रवासी कामगार फंसे हुए हैं। प्रवासी लीगल सेल ने याचिका में कहा है कि इन प्रवासियों के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ये प्रवासी श्रमिक वहां नाजुक स्थितियों में रह रहे हैं।

हर तीन-चार दिनों में शीर्ष कोर्ट के कामकाज की समीक्षा करेंगे सीजेआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एसए बोबडे अन्य न्यायाधीशों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क कर हर तीन चार दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की समीक्षा करेंगे। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव अशोक अरोरा ने दी। उन्होंने कहा कि बार के नेताओं एवं अन्य निकायों की ओर से सुझाव दिया गया है कि इस वर्ष ग्रीष्मावकाश की कुछ समय तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए और तब तक कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखा जाना चाहिए।

बंगाल केमिकल बनाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोलकाता स्थित बंगाल केमिकल में भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है।

बंगाल केमिकल की ओर से शुक्रवार को दी गई जानकारी में बताया गया है कि कंपनी प्रति महीने डेढ़ करोड़ टेबलेट बना सकती है। अब तक बंगाल केमिकल में क्लोरोक्विन फास्फेट-250 बनाई जाती थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन फास्फेट की रासायनिक संरचना एक ही है, केवल हाइड्रोक्सी अतिरिक्त तौर पर लगाया जाता है। अब यहां कोरोना की दवा भी बनेगी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा निर्मित यह कंपनी लंबे समय से दवा के कारोबार में जुटी रही है। कहा जा रहा है कि कच्चा माल (रॉ मैटेरियल) लाने में कुछ समस्याएं हो रही हैं।

दुनिया सेहतमंद चाहते हैं तो जंगली जानवरों को छोड़ दें अकेला

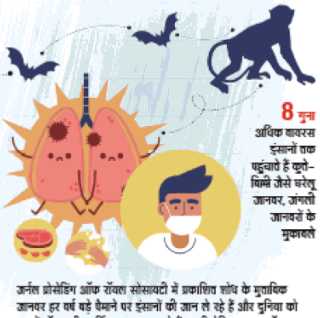

यह बात दुनिया में आम हो चुकी है कि वुहान के सी फूड मार्केट से घातक कोरोना वायरस दुनिया में फैला। चीन के मीडिया के अनुसार चमगादड़ खरीदने वाली एक महिला दुनिया की पहली मरीज (जिसे जीरो पेशेंट नाम दिया गया) थी। उसे शुरुआत में हल्की-सर्दी खांसी हुई, एक-दो दिन आराम करने के बाद वह फिर से सी फूड मार्केट में आई और वुहान को धीरे-धीरे कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। यदि आपको चीन के मीडिया की इस रिपोर्ट पर विश्वास न हो तो भी यह बात पूरी तरह सच है कि जंगली जानवरों से इंसान की छेड़छाड़ उसे ही बहुत भारी पड़ रही है।

जर्नल प्रोसेडिंग ऑफ रॉयल सोसायटी में प्रकाशित शोध के मुताबिक जानवर हर वर्ष बड़े पैमाने पर इंसानों की जान ले रहे हैं और दुनिया को अरबों डॉलर की आर्थिक चपत लगा रहे हैं। यूसी डेविस स्कूल ऑफ वेटनरी साइंस के वन हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. क्रिश्चियन क्रूयडेर के मुताबिक कोरोना की तरह की बीमारियां जानवरों के प्राकृतिक निवास और रहन-सहन में इंसान के सीधे हस्तक्षेप का नतीजा है।

2,90,000 जानवरों के प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं

30% कम से कम होना चाहिए वन क्षेत्र किसी भी देश में

दो अरब बीमार और दो करोड़ की मौत

आप कोरोना वायरस को ही खौफनाक मानते हैं तो यह आंकड़ा पढ़ लें। फॉरेन वायरस (जो घरेलू और जंगली जानवरों से इंसानों में आए) के कारण हर साल दुनियाभर में दो अरब लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से दो करोड़ लोग मारे जाते हैं। ये वायरस इंसानों को एचआइवी से लेकर इबोला तक से मार रहे हैं, इसका एक ही कारण है इंसानों का जानवरों की प्राकृतिक जीवनशैली में हस्तक्षेप।

कुत्ते हों या चूहे, बन जाते हैं मौत के फरिश्ते

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 1940 को आधार वर्ष मानते हुए अपने शोध को अंजाम दिया। नतीजे निश्चित रूप से डरावने हैं। कुत्ते, बिल्लियों, भेड़ों जैसे घरेलू जानवरों के साथ ही बंदरों-चूहों ने भी इंसान को काफी क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवर इंसानों से दूर थे लेकिन, इंसान ने ही कभी विकास, कभी जानवरों के व्यापार और कभी उन्हें बचाने के नाम पर जंगली जानवरों व अपने बीच मौजूद दूरी को खत्म कर दिया। प्लेग जैसी महामारी ने तो दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। वहीं यौन रोग एचआइवी बंदरों से इंसानों में आया।

चमगादड़ साबित हुए हैं खतरनाक

चमगादड़ पिछले तीन दशक से काफी परेशान कर रहे हैं। सार्स हो या निफा वायरस या फिर इबोला सभी ने बड़े पैमाने पर इंसानों की जान ली। हालांकि इन सभी पर इंसानों ने कंट्रोल पाया और ये ज्यादा क्षेत्र आधारित बीमारियां साबित हुईं। इबोला के कारण दो वर्ष तक पूरा अफ्रीका महाद्वीप खतरे में रहा था। अब जाकर इसका वैक्सीन और इलाज खोजा जा सका है।

पूर्ण प्रतिबंध

कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 200 से अधिक वाइल्ड लाइफ संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि जंगली जानवरों के व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। परंपरागत चिकित्सा के नाम पर दी जानी वाली किसी भी छूट पर भी पाबंदी लगे। अहम है कि चीन में शेरों से लेकर व्हेल तक का इस्तेमाल परंपरागत चिकित्सा के लिए किया जाता है और इसी आधार पर इनका व्यापार कानूनी बना दिया गया है। चीन का जानवरों का बाजार दुनियाभर में बदनाम है। भारतीय बाघों की भी चीन के दवा बाजार में बहुत मांग है। इसके कारण भारतीय बाघों का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है।

(स्रोत: गार्जियन/ब्लूमबर्ग)

जंगली जानवरों से इंसानों में आए 142 वायरस

वर्ष 1940 के बाद से इंसानों में 142 वायरस आ चुके हैं, कुछ ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो कुछ ने कम। कई को इंसानी शरीर ने स्वीकार कर लिया, तो कई के तोड़ हमने खोज निकाले लेकिन, अब भी कई बहुत जानलेवा हैं, जिनसे बचाव ही इलाज है। चाहे वो कोरोना हो या एचआइवी। चूहे, बंदर और चमगादड़ इंसानों में फैलने वाले 75 फीसद वायरस के लिए जिम्मेदार हैं।

इन वायरसों ने ढाया है कहर

इबोला, एचआइवी, बोविन टीबी, रैबिज, लेपटोसिरोसिस, स्वाइन फ्लू, हंटा वायरस, पीजन फ्लू, वेस्ट नाइल इंस्फेलाइटिस, साइट्टोडोमाईकोसिस, वाइट नोस सिंड्रोम, एंथ्रेक्स, डेविल फेस, कैनिन डिस्टेंपर, क्लेमेडिया, सारकोप्टिक मेंगे, प्लेग, ई-कोलाई।

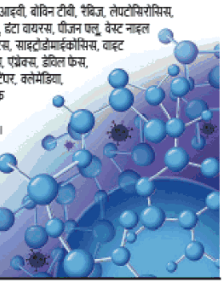

पर्यटकों के लिए जलियांवाला बाग 15 जून तक रहेगा बंद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के चलते जलियांवाला बाग के नवीनीकरण का काम समय से पूरा न हो पाने के चलते सरकार ने इसे अब 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले इसे नवीनीकरण से जुड़े कार्य के लिए 12 अप्रैल तक के लिए ही बंद किया गया था। इसे 13 अप्रैल 2020 को नरसंहार के शताब्दी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खोला जाना था, लेकिन सरकार ने कार्य पूरा होने तक यानि 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है।

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, देश फिलहाल जलियांवाला नरसंहार की शताब्दी वर्ष बना रहा है। इसके तहत इसका नए सिरे से संवारने का काम चल रहा था। जिसे 12 अप्रैल तक पूरा कर लेना था, लेकिन कोरोना के चलते यह काम समय पर नहीं हो सका। योजना के मुताबिक, इसे नवीनीकरण के बाद 13 अप्रैल को खोला जाना था। बता दें कि 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। इस दिन यहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धाजंलि देने आते है।

पूरी तरह स्वस्थ हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' वाले तन्मय वेकारिया

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : सोनी सब पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के बाघा यानी तन्मय वेकारिया को लेकर खबरें थीं कि वह सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। हालांकि, दैनिक जागरण से बातचीत में तन्मय ने स्पष्ट किया है कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दरअसल, कांदिवली वेस्ट में तन्मय की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि उनकी सोसाइटी में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सात अप्रैल को पहला मामला सामने आने के बाद उनकी सोसाइटी को सील कर दिया गया था। तन्मय ने कहा, 'सोसाइटीवासियों को 14 दिनों के लिए घरों में ही रहने को कहा गया है। पिछले 22 दिनों से हम अपने घरों में ही हैं। जिस परिवार के सदस्य को कोरोना संक्रमण हुआ है, मैं उनके संपर्क में नहीं आया हूं।'

जनमत मुद्दा

क्या पूर्व में पैदा हुई महामारियों से लड़ने की इंसानी जिजीविषा कोरोना महामारी के समूल नाश में दुनिया के लिए संबल बनी हुई है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

पंजाब ने एक मई तक बढ़ाया कर्फ्यू

अहम कदम ▸ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जताई कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका

राजस्थान व उत्तराखंड ने दिए 15 दिन तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत

जेएनएन, नई दिल्ली

कैप्टन अमरिंदर सिंह — फाइल

कोविड-19 वायरस के संक्रमण से भयावह होते हालात को देखते हुए ओडिशा के बाद दूसरे राज्य भी अपने स्तर पर एहतियाती पाबंदियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है और राजस्थान व उत्तराखंड की सरकारें लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि हॉटस्पॉट बने कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू रखा जाएगा और अन्य क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां खत्म करने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। डॉक्टरों व अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली उच्चस्तरीय कमेटी हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद ही कोई फैसला होगा। इससे पूर्व वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी महीने में हालात गंभीर चुनौतियों भरे हो सकते हैं। ऐसे हालात में किसी भी राज्य के लिए लॉकडाउन को खत्म करना आसान नहीं होगा। गुरुवार को 27 पॉजिटिव मामले आए, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। यह संकेत है कि राज्य कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा सकता है। स्थिति और गंभीर हो सकती है।

पंजाब में 87 और देश में 58 फीसद लोग हो सकते संक्रमित : कैप्टन ने चंडीगढ़ पीजीआइ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पंजाब में 87 फीसद लोगों और देशभर में 58 प्रतिशत लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। इन दावों पर विवाद छिड़ा तो उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके कहा कि कैप्टन ने जिस आकलन का उल्लेख किया है, वह पीजीआइ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स डॉ. शंकर प्रिंजा और उनकी टीम की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हालांकि शाम को पीजीआइ ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है।

लॉकडाउन से अलग है कर्फ्यू

लॉकडाउन में लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है, लेकिन जरूरी सेवाएं बंद नहीं होतीं। बैंक, डेयरी, दवा, राशन, फल-सब्जी व अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहती हैं। इसका पालन नहीं करने पर जेल हो सकती है। वहीं, कर्फ्यू इससे आगे का कदम है। इसमें लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। छूट बहुत कम देर के लिए दी जाती है। अति आवश्यक सेवा ही चालू रहती है। अति गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है।

मुंबई में धारावी और वरली-कोलीबाड़ा में घर-घर जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- जुमे की नमाज को लेकर झुग्गी बस्ती में चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस
- लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी ली जा रही है मदद
- अजीत पवार ने बारामती में भीलवाड़ा पैटर्न अपनाने को कहा

महाराष्ट्र खासकर मुंबई में कोरोना महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महानगर ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना के बढ़ते मामलों में राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए धारावी समेत कुछ अन्य इलाकों में घर-घर की जांच शुरू कर दी गई है।

धारावी एवं वरली कोलीबाड़ा सहित कई इलाकों में घर-घर जांच की जांच में कोरोना जैसे लक्षण वाले 292 लोग पाए गए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के नजदीक प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहनेवाले सभी लोगों की जांच के दौरान 60 फीसद लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

मुंबई की सबसे सघन झुग्गी बस्ती धारावी में घर-घर जांच की मुहिम शुक्रवार को भी जारी रही। इस क्षेत्र में 11 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए। इनमें से दो व्यक्ति दिल्ली के तबलीगी जमात से लौटे थे। इस इलाके में 45 फीसद से अधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। शुक्रवार की सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध के लिए धारावी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस ने धारावी के प्रमुख मार्गों पर मार्च भी किया। अत्यंत संकरी गलियों वाली धारावी की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इन प्रयासों का असर धारावी पर दिखाई दिया और सड़कों पर सन्नाटा नजर आया।

मुंबई में कोरोना रोगियों की सर्वाधिक संख्या वाली झोपड़पट्टी वरली कोलीवाड़ा में भी घर-घर जांच का सिलसिला चल रहा है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गृह क्षेत्र बारामती लोकसभा क्षेत्र में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए भीलवाड़ा पैटर्न अपनाने के निर्देश दे दिए हैं।

विदेश से भारतीयों को लाने पर फैसला हालात की समीक्षा के बाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 20,400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भारत से निकाला गया है। जबकि विदेश से भारतीयों को लाने का फैसला हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

रोजाना की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दम्मू रवि ने बताया, 'कई देशों की सरकारों ने अनुरोध किया था। लिहाजा हमने गुरुवार तक 20,473 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। यह एक लगातार जारी प्रक्रिया है। कुछ सवाल विदेश में रह रहे भारतीयों के बारे में आए हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हम निश्चित जवाब नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन अभी जारी है। हमें हालात की समीक्षा करने की जरूरत है... इसका फैसला सरकार करेगी कि अन्य देशों से भारतीयों को वापस लाने का प्रबंध हम कैसे करें। इन सभी देशों में हमारे राजदूत और उच्चायुक्त विदेश में सभी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में हैं और उन्हें हर सहायता प्रदान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के कोविड नियंत्रण कक्ष में हेल्पलाइंस भी सक्रिय हैं, टीमें इन मामलों में मार्गदर्शन कर रही हैं। स्थिति नियंत्रण में है। उनकी वापसी के बारे में हम बाद के चरण में समीक्षा करेंगे।'

देश में 37,978 राहत शिविर संचालित : गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि नौ अप्रैल तक विभिन्न राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक देशभर में 37,978 आश्रय और राहत शिविर संचालित हैं जिनमें प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंद लोगों को ठहराया गया है। इनमें से 34 हजार राहत शिविरों को राज्य सरकारों और 3,978 को गैर सरकारी संगठनों ने स्थापित किया है। देश में 26,225 खाद्य शिविर संचालित हैं जहां एक करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से 14,799 को राज्य सरकारें और 11,426 शिविरों को गैर सरकारी संगठन संचालित कर रहे हैं। करीब 16.5 लाख कामगारों को उनके नियोक्ताओं और उद्योगों ने आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराया है।

अब तक 1,44,910 सैंपलों की जांच

प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 146 लैब कार्यरत हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 67 लैब को भी जांच की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात नौ बजे तक कुल 1,44,910 सैंपलों की जांच की गई थी।

कोरोना संदिग्ध गर्भवती की मौत के मामले की जांच हो : महिला आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने नौ महीने की एक गर्भवती की मौत के मामले में जांच की मांग की है। महिला कोरोना संदिग्ध थी और उसे इलाज के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 27 वर्षीय गर्भवती को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद उसे अलग-अलग अस्पतालों में ले जाना पड़ा। इस दौरान उसे नालासोपारा से मुंबई के बीच 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। अगले दिन दोपहर में महिला की मौत हो गई और गर्भस्थ शिशु को भी नहीं बचाया जा सका।

इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महिला आयोग ने मामले की जांच की मांग की है। महिला आयोग ने ट्वीट किया, 'महाराष्ट्र में नौ महीने की एक गर्भवती को दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ा। संदेह है कि उसे कोरोना संक्रमण था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इससे भी दुखद रहा कि उसे अस्पतालों तक पहुंचने और इलाज पाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा।'

अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सोशल के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग की करेगी बात

नईदुनिया, रायपुर

▸ 'दैनिक जागरण' की पहल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत

भूपेश बघेल — फाइल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दैनिक जागरण और उसके सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक जागरण समूह सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) शब्द का प्रयोग कर रहा है, जोकि सही है। अब हमारी सरकार भी इसी शब्द का उपयोग करेगी।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन दैनिक जागरण समूह ने सबसे पहले इस शाब्दिक त्रुटि को सुधारा था। दैनिक जागरण और नईदुनिया ने फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) लिखना शुरू किया। सीएम बघेल ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा है कि यह अच्छी सोच है।

सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी है। हम अपने ही समाज के लोगों को अपने से कैसे दूर कर सकते हैं। इसकी जगह शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस की जरूरत है। इस शब्द को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अब अपना लिया है।

कोरोना संकट : आधे अरब लोग हो जाएंगे गरीब

कोरोना के कारण दुनिया के ज्यादातर उद्योग-धंधे ठप पड़े हैं। शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट का दौर है और कई लोगों के सामने अभी से रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह स्थिति बद से बदतर हो सकती है। साथ ही आर्थिक विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि दुनिया गंभीर आर्थिक मंदी का शिकार हो सकती है। ऐसे वक्त में ऑक्सफैम की चेतावनी ने और चिंता बढ़ा दी है। ऑक्सफैम के अनुसार कोविड-19 संकट से निपटने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली मंदी दुनिया के करीब आधे अरब लोगों को गरीबी में धकेल देगी। यह दुनिया की 8 फीसद आबादी है।

कई देशों पर बहुत बुरा प्रभाव

किंग्स कॉलेज लंदन और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया है, जिसमें उन्होंने विश्व बैंक की गरीबी रेखा पर 1.90 डॉलर, 3.20 डॉलर और 5.50 डॉलर प्रति दिन के आधार पर वैश्विक मौद्रिक गरीबी पर कोरोनो वायरस के अल्पकालिक प्रभाव का अनुमान लगाया है। वैश्विक स्तर पर प्रगति के एक दशक तक के विश्लेषण के अनुसार 1990 के बाद पहली बार सभी तीन परिदृश्यों के तहत वैश्विक गरीबी का स्तर बढ़ेगा। इसका असर दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, सब-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व में और भी बुरा होना तय है, जहां यह 30 साल तक की तरक्की को खत्म कर सकता है।

यह होगा परिणाम

सबसे गंभीर परिदृश्य में आय में 20 फीसद की गिरावट शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 54 करोड़ लोग प्रति दिन 5.50 डॉलर (417 रुपये) की विश्व बैंक की गरीबी सीमा से कम कमाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि संकट के दौरान विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है और अफ्रीका के करीब आधे रोजगार खो सकते हैं।

संकट से निपटने की तैयारी

अगले सप्ताह ऋण राहत पर चर्चा के लिए जी-20 देशों के मंत्रियों, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की बैठक होगी। ऑक्सफैम ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आर्थिक पतन को रोकने के लिए बताई गई राशि जुटाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया है। धन जुटाने के संभावित उपायों में 1 ट्रिलियन डॉलर के ऋण को तत्काल रद्द करना शामिल हो सकता है।

आधे अरब लोगों को गरीबी में धकेल सकता है कोरोना संकट

कोविड-19 के कारण 20 फीसद आय में गिरावट से अतिरिक्त लोग गरीबी में आएंगे

क्षेत्र	करोड़
पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र	23.98 करोड़
दक्षिण एशिया	12.88
लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र	5.43
मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका	4.49
सब सहारा अफ्रीका	4.46
यूरोप और मध्य एशिया	3.05
अन्य	0.47

₹417 (5.50 डॉलर) प्रति दिन से कम कमाने वाले हैं गरीबी

(स्रोत: ऑक्सफैम)

राहत

शहरों में दैनिक जीवनयापन करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए 48.17 करोड़ रुपये

योगी ने 4.81 लाख गरीबों के खाते में भेजे एक-एक हजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदार हैं शामिल

योगी आदित्यनाथ — फाइल

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों में दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वालों की शुक्रवार को आर्थिक मदद की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणी के 4.81 लाख से अधिक गरीबों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि भेजी। यह धनराशि स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक एवं मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों को दी गई है।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित इन शहरी गरीबों की 48.17 करोड़ रुपये से अधिक की मदद की। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पांच कालिदास मार्ग से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग जिलों के लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को भोजन और भरण-पोषण भत्ता सरकार मुहैया करा रही है। इसमें रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदार शामिल हैं। इन्हें एक-एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता दिया जा रहा है।

योगी ने कहा कि इससे पहले सरकार ने 35 लाख मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता दिया था। 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 1.65 करोड़ से ज्यादा अंत्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन भी मुहैया कराया जा रहा है।

किसानों को तीन माह तक मिलेंगे दो-दो हजार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 2.34 करोड़ किसानों को तीन माह तक दो-दो हजार रुपये देने की व्यवस्था सरकार ने की है। जनधन खाते में प्रति माह तीन महीने तक 500 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस मुहैया कराई जा रही है। इस संकट में केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। हर जिले में कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अक्षय ने बीएमसी को दिए तीन करोड़ रुपये

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

- स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पीपीई के उत्पादन में मिलेगी मदद
- पीएम केयर्स फंड में भी 25 करोड़ रुपये दान दे चुके हैं अभिनेता

कोरोना वायरस से जंग के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये दान देने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने अब बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) को भी तीन करोड़ रुपये दान किए हैं। इस राशि से स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (पीपीई), मास्क, दस्ताने और रैपिड टेस्टिंग किट के उत्पादन में मदद मिलेगी।

जागरण समूह के अखबार मिड डे ने बीएमसी के च्वाइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर आशुतोष सलील के हवाले से कहा कि कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने बीएमसी कमिश्नर से संपर्क कर दान दिया था। उनका दान जनरल फंड में जाएगा, जिसका उपयोग पीपीई, मास्क, गलव्स और रैपिड टेस्टिंग किट के उत्पादन में होगा।

अक्षय ने पुलिस, डॉक्टर, नर्स, नगर निगम के कर्मचारियों समेत कोरोना की लड़ाई से जुड़े लोगों को दिल से थैंक यू बोलने की एक मुहिम भी शुरू की है। इसमें फिल्मी सितारे जुड़ते जा रहे हैं। दक्षिण भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी ने तेलंगना पुलिस को सलाम करते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा, 'कांस्टेबल का बेटा हूं और मैं पुलिस विभाग को सलाम करता हूं। पुलिसकर्मियों की सतर्कता की वजह से कोरोना वायरस के नियंत्रण में मदद मिल रही है। वे बिना सोए लगातार काम कर रहे हैं। मैं आम लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वे मुश्किल की इस घड़ी में पुलिस का सहयोग करें।'

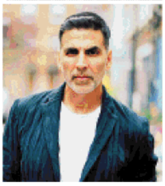

अक्षय कुमार। फाइल

सोनू सूद रोजाना 45,000 लोगों को खिलाएंगे खाना

डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को अपना होटल रहने के लिए देने के बाद अब अभिनेता सोनू सूद ने जरूरतमंदों की मदद के लिए भोजन और राशन बांटने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपने दिवंगत पिता शक्ति सागर सूद के नाम से यह पहल शुरू की है। इसके तहत मुंबई में रोजाना 45,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाएगा।

अब आलिया के ट्वीट पर मुंबई पुलिस की हाजिरजवाबी

इन दिनों मुंबई पुलिस अपनी हाजिरजवाबी से खूब सुर्खियां बटोर रही है। गुरुवार को आलिया भट्ट ने मुंबई पुलिस के एक ट्वीट को साझा करते हुए लिखा, 'धन्यवाद मुंबई पुलिस। प्यार और आभार को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। आइए इनके लिए हम अपने घरों में बैठें।' आलिया के इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस ने टिप्पणी की, 'मुंबईकर हमें उम्मीद है कि आप सब बिना जरूरत किसी भी गली में न घूमने की आलिया की राय से राजी होंगे। सभी अपनी डियर जिंदगी का ख्याल रखेंगे।' मुंबई पुलिस का यह जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि राजी, गली बॉय और डियर जिंदगी तीनों आलिया की फिल्मों के नाम हैं। इससे पहले अजय देवगन के ट्वीट पर भी मुंबई पुलिस ने उनकी फिल्मों के नामों को जवाबी टिप्पणी में पिरोया था।

इन 'शूरवीरों' को प्रतिदिन सलाम करता है एम्स

मधुकर दुबे, रायपुर

- डॉक्टर और स्टाफ नर्स का ताली और थाली बजाकर किया जाता है स्वागत
- ये नर्स कोरोना पॉजिटिव रोगियों की कर रही हैं सेवा

ये किसी युद्ध-भूमि में जंग लड़ने वाले शूरवीर नहीं, बल्कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना को पछाड़ने का अदम्य साहस दिखा रहे डॉक्टर और नर्स हैं। ये जब अस्पताल में कदम रखते हैं तो एम्स रायपुर का प्रबंधन इनका ताली बजाकर और सलामी देकर स्वागत करता है। एम्स में ये शूरवीर कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पूरी समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो सकें।

शुक्रवार सुबह का वक्त। घड़ी में 10.32 बजे थे। उसी समय 'शूरवीरों' के एक दल ने एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कार्यालय में कदम रखा। 35 डॉक्टर और स्टाफ नर्स के कदम दफ्तर में पड़ते ही वहां मौजूद हर कोई सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. करन पिपरे और प्रबंधन के अन्य अधिकारियों ने हॉल में आकर उनके स्वागत में ताली बजाकर सभी का हौसला बढ़ाया। इसके बाद किसी जुमले पर हंसाया।

डॉ. करन पिपरे ने इस मौके पर कहा- किसी भी विषम परिस्थिति में खुश रहने की आदत ही कामयाबी दिलाती है। यही मुस्कराहट लिए आप जब मरीजों से विनम्र और सेवाभाव से मिलते हैं तो उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चाहे किसी भी रोग का मरीज हो, जब वह अपने डॉक्टर के हंसमुख स्वभाव को देखता है तो उसके अंदर नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। नतीजा ये होता है कि दवा भी धीरे-धीरे मरीज पर सकारात्मक प्रभाव दिखाने लगती है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. किरन पिपरे व अन्य स्टाफ ने कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ का स्वागत सलामी देकर किया। नई दुनिया

अब भारत में होगा प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज

निदान ▸ गंभीर रूप से बीमार मरीजों का नई विधि से उपचार

आइसीएमआर ने दी अनुमति, जल्द जारी होगी इसकी विस्तृत गाइडलाइन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अब देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज का रास्ता साफ हो गया है। केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आइसीएमआर ने इसकी अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) कभी भी इसे हरी झंडी दे सकता है। फिलहाल इस थेरेपी का इस्तेमाल केवल गंभीर रूप से बीमार और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए ही किया जाएगा।

आइसीएमआर के वैज्ञानिक डॉ. मनोज मुरहेकर के अनुसार दुनिया के कई देशों में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर पाया गया है। लेकिन भारत में अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके अनुसार केरल सरकार के अनुरोध पर आइसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अनुमति दे दी है और डीसीजीआइ से इसकी अनुमति मांगी गई है। आइसीएमआर देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के लिए विस्तृत गाइडलाइन को अंतिम रूप देने में जुटा है।

डॉ. मनोज ने साफ कहा है कि प्लाजा थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ क्लीनिक ट्रायल के लिए किया जाएगा। इसके बाद नतीजों के आने के बाद ही इसे कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दी जाएगी।

क्या है प्लाज्मा थेरेपी

प्लाज्मा थेरेपी खून की प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के आधार पर शरीर में किसी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है। दरअसल किसी भी वायरस के प्रवेश करने के बाद शरीर खुद उससे लड़ने लगता है और उस वायरस को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। जैसे ही एंटीबॉडी वायरस के खत्म करने में सफल होता है, मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। जाहिर है कोरोना वायरस की चपेट में आकर ठीक हुए हजारों लोगों के शरीर में यह एंटीबॉडी मौजूद है। यदि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज में किसी तरह यह एंटीबॉडी पहुंचा दिया जाए, तो वह व्यक्ति स्वतः ही कोरोना से ठीक हो सकता है। इस थेरेपी के तहत कोरोना से ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा अलग किया जाता है और फिर उस प्लाज्मा को पीड़ित मरीज के शरीर में पहुंचाया जाता है। प्लाज्मा के साथ एंटीबॉडी के शरीर में पहुंचने के बाद मरीज ठीक होने लगता है। दरअसल वैक्सीन भी इसी तरह शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। लेकिन कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं होने के कारण इसके प्रकोप को रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोरोना का दूसरा पहलू यह भी है कि 80 फीसद कोरोना के मरीज सामान्य इलाज से खुद ही ठीक हो जाते हैं। यानी उनके शरीर में अपने-आप एंटीबॉडी बन जाता है। जाहिर है ऐसे ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा में मौजूद कोरोना के वायरस का एंटीबॉडी गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

देश में कुल संक्रमित

राज्य	संक्रमित
महाराष्ट्र	1574
तमिलनाडु	911
दिल्ली	903
राजस्थान	561
मध्य प्रदेश	483
तेलंगाना	487
उत्तर प्रदेश	436
आंध्र प्रदेश	381
केरल	364
गुजरात	378
कर्नाटक	207
जम्मू-कश्मीर	207
हरियाणा	165
पंजाब	151
बंगाल	116
बिहार	60
ओडिशा	44
उत्तराखंड	35
हिमाचल प्रदेश	29
असम	28
चंडीगढ़	18
छत्तीसगढ़	18
लद्दाख	15
झारखंड	14
अंडमान-निकोबार	11
गोवा	7
पुडुचेरी	7
मणिपुर	2
त्रिपुरा	2

बिहार में एक परिवार के 21 तो पंजाब के एक ही गांव में 32 संक्रमित

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 60 हो गई है। इनमें एक ही परिवार के 21 लोग हैं। ओमान से सिवान के अपने गांव लौटे एक युवक ने परिवार के 20 और गांव के 2 अन्य लोगों को संक्रमित किया। यानी उस युवक समेत कुल 23 लोग संक्रमित हुए। शुक्रवार को सिवान से आए दो और सैंपल पॉजिटिव पाए गए। ये लोग उसी परिवार से हैं, जिनका एक व्यक्ति पिछले दिनों ओमान से लौटा था।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इससे पहले गुरुवार को राज्य में कोरोना के 19 नए पॉजिटिव केस मिले थे। इनमें सर्वाधिक मामले सिवान के थे। सिवान के जिस रघुनाथपुर के पंजवार से सर्वाधिक मामले अब तक मिले हैं, मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र से किसी के बाहर आने या अंदर जाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

पंजाब के एक ही गांव में 32 पॉजिटिव : पंजाब में शुक्रवार को 20 और पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें दस मोहाली के जवाहरपुर गांव के हैं। तीन हजार की आबादी वाले इस गांव में 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पूरे मोहाली जिले में 48 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 151 पहुंच गई है। इनमें 27 जमाती हैं।

छत्तीसगढ़ के कटघोरा में कर्फ्यू जैसे हालात

नईदुनिया, कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित कटघोरा में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव नौ केस सामने आने के बाद इसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। कटघोरा सील करने के बाद चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। यही वजह है कि शुक्रवार को यहां कर्फ्यू जैसे हालात रहे। ड्रोन से दिनभर निगरानी की गई। कटघोरा के रहमनिया वार्ड के 192 लोगों के सैंपल लिए गए। 34 परिवारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। यहां की आबादी करीब ढाई हजार है। सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि कटघोरा की जामा मस्जिद में कमाठी महाराष्ट्र से आए 16 तब्लीगी जमाती मिले थे। इनमें से 16 वर्षीय किशोर चार अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।

'डब्ल्यूएचओ के साथ वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी'

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शुक्रवार को बताया कि विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहा है।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में डॉ. हर्षवर्धन ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि जब तक हम वैक्सीन विकसित नहीं कर लेते तब तक हमें शारीरिक दूरी और लॉकडाउन नियमों का पालन करने की जरूरत है। ये सोशल वैक्सीन हैं। हमें सुरक्षा उपायों का पालन करने की जरूरत है।' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शिकायत की कि विभिन्न राज्यों में लोग लॉकडाउन की भावना का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम कई राज्यों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग लॉकडाउन के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने राज्यों में लॉकडाउन का सौ फीसद पालन सुनिश्चित कराएं। अगर हम इसमें पिछड़ गए तो कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना हमारे लिए कठिन हो जाएगा।' हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र ने 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है और सभी राज्यों को 4,100 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हर राज्य को दूसरे राज्य की अच्छी चीजों का अनुपालन करना चाहिए। मैं सभी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे ताजा गाइडलाइंस और सुझावों के लिए नियमित तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।'

कोरोना से जारी जंग जीतने के लिए सेवानिवृत्त जांबाजों को बुलाएगी सेना

निशांत यादव, लखनऊ

- रक्षा मंत्रालय ने हेल्पलाइन बनाकर देशभर से पूर्व सैनिकों को स्वयंसेवी के रूप में बुलाया

कोरोना से जारी जंग जीतने के लिए अब सेना के वे जांबाज भी मोर्चा संभालेंगे, जो कई साल तक मातृभूमि की रक्षा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। मेडिकल कोर के अलावा अन्य यूनिटों के पूर्व सैनिक, जेसीओ और अफसर वालंटियर के रूप में इस जंग में शामिल होंगे। सेना ने इनकी भर्ती के लिए सेल भी बना दिया है। मेडिकल कोर के कर्नल रैंक के अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है।

मेडिकल कोर के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी, लैब तकनीशियन, नर्सिंग सहायक व पैरा मेडिकल स्टाफ को सैन्य अस्पतालों के साथ इनसे संबद्ध निजी अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। कोरोना की जांच से लेकर उपचार में ये अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं अन्य यूनिट के पूर्व सैनिकों को संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन में भेजने के साथ लॉकडाउन में कानून व्यवस्था संभालने में लगाया जाएगा। सेना ने पूर्व सैनिकों से संपर्क कर उनका डेटा बैंक बनाने का काम शुरू भी कर दिया है।

ऐसे करें संपर्क : मेडिकल कोर के कर्नल ओम प्रकाश के नेतृत्व में वालंटियर सेल ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका हेल्पलाइन नंबर भी शुरू कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर 8948986999 और 9793638339 पर पूर्व सैनिक, जेसीओ और जवान संपर्क कर सकते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक जो अभी रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में अपनी सेवा दे रहे हैं, वह भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। इन नंबर पर पूर्व सैनिक को अपनी ट्रेड और ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल पर सेना एक फॉर्म भेजेगी, जिसे भरकर वापस करना होगा। फॉर्म के आधार पर पूर्व सैनिक का डेटा तैयार होगा। इससे उनको नजदीकी या दूसरे प्रदेशों में सहयोग के लिए बुलाया जाएगा। पूर्व सैनिक प्रमोद श्रीवास्तव कहते हैं कि हम देश के काम आएं, इस पर हमें गर्व होगा।

सख्त रुख...

कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस पूरी सख्ती से सबक सिखा रही है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समूह में निकलीं इन महिलाओं और युवतियों को जब महिला पुलिसकर्मी ने रोका और पूछा कि कहां जा रही हो तो समुचित जवाब नहीं मिला। इस पर पुलिसकर्मी ने इन्हें घरों में रहने की हिदायत देते हुए कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। दुर्गेश शुक्ला

सफाई में लापरवाही बरत रहे कांस्टेबल की शिकायत

नईदुनिया, दमोह

- कहा-ड्यूटी से आने के बाद सीधे घर में घुस जाते हैं, मुझे बच्चों की चिंता है
- दमोह के एसपी ने एक सप्ताह तक घर नहीं जाने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश के दमोह जिला पुलिस बल में शामिल एक कांस्टेबल द्वारा ड्यूटी से घर आने पर साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने से नाराज उसकी पत्नी ने एसपी से शिकायत की है। उसने कहा है कि ड्यूटी से आने के बाद पति सीधे घर में घुस जाते हैं। इससे मुझे बच्चों की चिंता होती है। अब एसपी ने उस कांस्टेबल को जिला मुख्यालय पर ही रोक दिया है।

लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले के एक थाना क्षेत्र में पदस्थ कांस्टेबल को जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया था। कांस्टेबल प्रतिदिन ड्यूटी के बाद अपने घर चला जाता था, लेकिन इस दौरान वह बिना सुरक्षा उपाय किए सीधे घर में प्रवेश कर जाता था। अपनी वर्दी को परिवार के अन्य लोगों के कपड़ों के साथ रख देता था। इस पर कांस्टेबल की पत्नी ने आपत्ति जताई, लेकिन वह नहीं मान रहा था। इससे परेशान पत्नी ने सीधे एसपी से गुहार लगाई और कांस्टेबल पति की शिकायत की। एसपी हेमंत चौहान ने अब कांस्टेबल को जिला मुख्यालय पर ही रुकने का आदेश जारी किया है।

जिला मुख्यालय पर ही रहने के दिए गए निर्देश

एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि संबंधित कांस्टेबल को जिला मुख्यालय पर रहने के ही निर्देश दिए गए हैं और उससे कहा गया है कि आगामी एक सप्ताह तक वह अपने घर नहीं जाएगा। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि यदि कांस्टेबल के परिवार को किसी सामग्री की आवश्यकता होगी तो संबंधित थाने के प्रभारी उस जरूरत को पूरा करेंगे।

अहम योगदान

बिहार के डॉक्टर ने बनाई सस्ती पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपयोगी, अन्य कंपनियां बेच रही हैं दो से ढाई हजार में

स्वस्थ समाज

500 रुपये में सिर से पांव तक सुरक्षा

कीर्ति पांडेय, सिवान

कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में जरूरी साजोसामान के लिए अब भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को सिर से पांव तक सुरक्षा देने वाला अभेद्य कवच जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट कहते हैं, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का संक्रमण से सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है ताकि लोगों के उपचार में बाधा न आने पाए। बिहार के एक चिकित्सक ने महज 500 रुपये में यह किट तैयार कर दिखाई है, जिसका बाजार मूल्य दो से ढाई हजार रुपये है। उप्र ने एक लाख किट का ऑर्डर दिया है। अन्य राज्यों से भी इसकी मांग है।

संक्रमित मरीजों का उपचार करने वाले या उनके नजदीक जाने वाले हर व्यक्ति को इस किट की जरूरत होती है। फिलहाल पूरे देश में ऐसी लाखों किट की मांग है। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दाम भी औसतन दो से ढाई हजार तक है। ऐसे में सिवान के डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. रामेश्वर सिंह द्वारा महज 500 रुपये की लागत से तैयार इस पीपीई किट ने बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है। इसे चिकित्साजगत और सरकार द्वारा खरा पाया गया है। उप्र सरकार ने शुरुआती एक लाख का ऑर्डर दिया है, जिसकी आपूर्ति जल्द होने जा रही है।

डॉ. रामेश्वर सिंह की इस उपलब्धि को सिवान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हाथोंहाथ लेते हुए इसकी सूचना सभी जगह भेजी, जिसके बाद उप्र सहित अन्य राज्यों से इसकी मांग की जा रही है। दावा है कि किट पूरी तरह से चिकित्सकीय मानदंड पर खरी उतरी है।

डॉक्टर रामेश्वर बताते हैं कि जब उन्होंने इस किट की कमी के कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों का आकलन किया तो सोचा कि इस ओर कुछ किया जाए। इसके बाद पीपीई किट बनाने के लिए अध्ययन में जुट गए। दुनियाभर में मौजूद विकल्पों का इंटरनेट पर अध्ययन किया। मेडिकल जर्नल्स भी पढ़े और तब अनुभव के आधार पर किट तैयार करने में जुट गए। अपने अस्पताल श्री साईं हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में पहली किट की सिलाई कराई।

सिविल सर्जन और जिलाधिकारी के स्तर पर इसके मानदंड पर खरा उतरने की जांच की गई। वहां से सहमति मिलने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में निर्माण का काम शुरू करने का निर्णय किया। फिलहाल नोएडा (उप्र) में एक यूनिट में इसका निर्माण शुरू किया गया है। दिल्ली-एनसीआर से निर्माण सामग्री उपलब्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए एक लाख पीपीई किट के ऑर्डर की खेप लगभग तैयार है।

डॉ. रामेश्वर सिंह।

इस किट के निर्माण में किसी तरह का लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है और ना ही इसके लिए यह किया है। एक किट की लागत 500 रुपये पड़ रही है। बिना कोई लाभ निकाले इसे इसी मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं।

-डॉ. रामेश्वर सिंह, सिवान, बिहार

बिहार के सिवान स्थिति श्री साई हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर द्वारा बनाई गई पीपीई किट खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों को भी बड़ी संख्या में ऑर्डर दिया गया है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए यह किट अत्यंत आवश्यक है।

-श्रुति सिंह, एमडी, उप्र मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड

इस तरह प्रदान करती है सुरक्षा

किट में फेस मास्क, बॉडी गाउन, पारदर्शी हेलमेट शील्ड, हैंड ग्लब्स, जूता कवर शामिल हैं। यह आवरण सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए होता है। इन सामग्रियों को तैयार करने के लिए 60 जीएसएम का लेमिनेटेड नॉन बोवेन फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वायरस भेद नहीं सकता है।

डॉ. रामेश्वर सिंह की पीपीई किट पहनकर दिखाता अस्पताल का कर्मचारी। सौजन्य : सभी फोटो स्वयं

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

राजस्थान में एक दिन में 98 केस

प्रथम पृष्ठ का शेष

राजस्थान में 98 नए केस मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 561 हो गई है। 20 नए मरीजों के साथ पंजाब में 151 संक्रमित हो गए हैं। हरियाणा में सात नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमित 165 हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर में 23 नए मामलों में सात जमाती हैं। बिहार में भी संक्रमितों की संख्या 60 हो गई है। जबकि, मध्य प्रदेश में 27 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 483 हो गई है। पुडुचेरी में भी दो नए केस मिले हैं और संक्रमितों की संख्या सात हो गई है। वहीं, बंगाल में भी 12 नए मामले मिलने की खबर और वहां कुल 116 संक्रमित हो गए हैं। असम में कोरोना से पहली मौत हुई है>

अंडमान में 10 संक्रमित स्वस्थ : अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अच्छी खबर मिली है। वहां कोरोना से संक्रमित पाए गए 11 मरीज में से 10 पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।

मप्र, छग और बंगाल में निकला लॉकडाउन का जनाजा

घोर लापरवाही ▶ बंगाल और मप्र में नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए लोग, छग में जनाजे और शब-ए-बारात के लिए जुटी भीड़

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 219 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

जेएनएन, नई दिल्ली

देश कोरोना से जूझ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का ही जनाजा निकालने पर तुले हैं। मध्य प्रदेश और बंगाल में जहां सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। वहीं, छत्तीसगढ़ में जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा मनाही के बावजूद शब-ए-बारात के लिए भी लोग इकट्ठा हुए। ऐसे में प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाते हुए मप्र में 53 और छत्तीसगढ़ में 166 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई और सागर में 53 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चौरई में 40 और सागर में 13 लोगों पर कार्रवाई की गई है। चौरई थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि लोग गुरुवार को खैरी मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए। इन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया। भीड़ में ग्राम खैरीगढ़ सरपंच एजाज खान भी था। सरपंच के सहित 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर, सागर में भी सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को मोतीनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत आंबेडकर वार्ड में गरीबों के लिए बने आवास की छत पर कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की थी। आसपास रहने वालों ने इसके वीडियो बनाकर शिकायत की थी। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मध्य प्रदेश के सागर में घर की छत पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते लोग। सौ. सोशल मीडिया

मुर्शिदाबाद में नमाज के लिए सैकड़ों लोग हुए जमा

बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की नमाज के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए मस्जिद के इमाम और वहां जमा हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें क्षेत्र खाली करने का आग्रह किया फिर भी नमाजी नहीं माने। युवा पुरुष और बुजुर्ग लोग, जो गंभीर रूप से घातक वायरस से प्रभावित होने के जोखिम में हैं, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मस्जिद में देखे गए। पुलिस ने कहा कि प्रत्येक मस्जिद में नजर रखना आसान नहीं है। यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण वहां कई मस्जिदें हैं।

छत्तीसगढ़ में 166 लोगों पर मुकदमा दर्ज : छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को लॉकडाउन के उल्लंघन पर 166 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि 30 मार्च को कोरबा की पुरानी बस्ती मस्जिद के नजदीक रहने वाले एक 67 साल के बुजुर्ग का निधन होने पर कब्रिस्तान में 150 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। इसमें महाराष्ट्र के कामठी से आए संक्रमित जमाती किशोर समेत पुरानी बस्ती व कोरबा के लोग शामिल हुए थे। ऐसे में पुलिस ने सभी 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, बिलासपुर के रतनपुर जूना शहर स्थित मुशा शहीद की दरगाह पर शब-ए-बारात के उपलक्ष्य में गुरुवार रात जुटे 16 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसपी, बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल ने बताया गया कि दरगाह पर जुटे आरोपितों से पूछताछ की गई।

छत्तीसगढ़ में सभी जमातियों को खोज लिया गया : भूपेश बघेल

नईदुनिया, रायपुर : दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे सभी 107 तब्लीगी जमातियों की खोज कर ली गई है। सरकार की निगरानी में सभी को क्वारंटाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अब उन लोगों को खोज रही है, जो बीते 20 दिनों में निजामुद्दीन से लौटे लोगों के संपर्क में आए थे। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में अभी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं है।

मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि तब्लीगी जमात से जुड़े 159 लोगों की सूची राज्य को भेजी गई थी। यह सूची आंध्रप्रदेश की स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआइबी) ने मोबाइल टावर के डाटा के आधार तैयार की थी, जो पूरी तरह सही नहीं थी। इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी शामिल थे, जो केवल निजामुद्दीन स्थित दरगाह क्षेत्र से गुजरे थे। सूची में कुछ हिंदुओं के नाम भी दर्ज थे।

बुलंदशहर में तब्लीगी जमात के 1500 लोगों के मोबाइल नंबर पुलिस के निशाने पर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

कोरोना वायरस से जंग लड़ रही खाकी ने दिल्ली पुलिस की मदद से 1500 जमातियों के नंबर निशाने पर लिए हैं। इनमें से कुछ तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे तो कुछ अन्य जिलों में जमात के लिए गए थे। इनमें करीब 150 नंबरों को पुलिस सुन रही है, जबकि कुछ जमातियों को क्वारंटाइन किया है। अब पुलिस उन जमातियों की तलाश कर रही है, जो सामने नहीं आए हैं। दिल्ली स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में उप्र के बुलंदशहर से सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। लॉकडाउन के बाद कुछ जमाती वापस आ गए। बाकी छिपकर रह रहे हैं। वर्तमान में जिले में आठ कोरोना पॉजिटिव हैं। पुलिस को इनपुट मिला है कि अभी जिले के करीब 1500 जमाती ऐसे हैं, जो दूसरे जिलों और विदेश में जमात के लिए गए थे। वो वापस लौट आए हैं, लेकिन न तो वह अपने घर पहुंचे हैं और न ही रिश्तेदारी में हैं। इन सभी जमातियों के नंबरों का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स (सीडीआर) मोबाइल कंपनियों से मांगा गया है।

200 जमातियों की मिली सीडीआर : पुलिस को 200 नंबरों की सीडीआर मिल चुका है। पिछले दो माह में इनकी लोकेशन मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली, शामली, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर व बागपत में मिली है। पुलिस की एक टीम इन जिलों में जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से जमातियों की तलाश में जुटी है।

दिल्ली पुलिस की मदद से हासिल किए नंबर

सर्विलांस के सहारे कुछ जमातियों की तलाश की जा रही है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। किसी का भी नया इरादा सामने आएगा तो शासन को अवगत कराया जाएगा। -संतोष कुमार सिंह, एसएसपी

802 जमातियों के पास पासपोर्ट

सर्विलांस पर लिए गए नंबरों की आइडी निकलवाकर जब जांच की गई तो पता चला कि इनमें 802 के पास पासपोर्ट हैं। सीडीआर के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक यह लोग किसी दूसरे देश में तो नहीं गए, लेकिन अपने जिले में भी नहीं रहे हैं। पुलिस को इन पर शक है कि वह जानबूझकर छिपे हैं।

जमातियों के चलते संकट में हैं मदरसों के बच्चे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज से जुड़े जम्मू-कश्मीर के जमातियों द्वारा प्रदेश के मदरसों और दरगाहों (पाठशाला) तक कोरोना वायरस पहुंचाए जाने की आशंका है। इसलिए प्रदेश प्रशासन ने मदरसों और दरगाहों की जांच शुरू कर दी है। इनमें पढ़ाने वाले मौलवियों, अध्यापकों और छात्रों का पता कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को भी इस काम में लगाया गया है। जम्मू-कश्मीर में विभिन्न इस्लामिक संगठनों से जुड़े छोटे-बड़े करीब 1200 मदरसे और 2000 दरगाह हैं।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारी को उसके क्षेत्र में स्थित सभी पंजीकृत-गैर पंजीकृत मदरसों की सूची बनाने और उनमें पढ़ने-पढ़ाने वालों का ब्योरा तैयार करने को कहा गया है। उन्हें निर्देश है कि वह इन लोगों की मौजूदा स्थिति का भी पता लगाएं। इन सभी लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाएगा ताकि इन लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका से पूरी तरह निपटा जा सके। अधिकारी ने बताया कि यह कदम तब्लीगी जमात के सदस्यों के प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों, मदरसों व दरगाहों के साथ जुड़े होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुए उठाया गया है।

निजामुद्दीन पहुंचे थे प्रदेश के 1900 तब्लीगी : जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से संबंध रखने वाले तब्लीगी जमात के करीब 1900 सदस्य गत माह निजामुद्दीन मरकज में ही थे। इनके अलावा कई अन्य देश-विदेश में भी थे। प्रदेश में तब्लीगी जमात से जुड़े सदस्यों की संख्या करीब 45 हजार है। प्रदेश में अभी कोविड-19 के 209 मरीजों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा तब्लीगी जमात से जुड़े सदस्य, उनके परिजन या फिर उनके संपर्क में आए लोग ही हैं। बांडीपोरा में दो दर्जन से ज्यादा कोविड-19 मरीज हैं, उन सभी का प्रत्यक्ष-परोक्ष संबंध तब्लीगी जमात से ही है। श्रीनगर, बारामुला, कुपवाड़ा, शोपियां, ऊधमपुर, राजौरी में भी कोविड-19 के अधिकांश मरीज जमात से किसी ने किसी तरीके से जुड़े हैं। इनमें से कई स्थानीय दरगाहों और मदरसों में भी पढ़ाते हैं।

क्वारंटाइन होने से पहले मदरसों व दरगाहों में गए थे तब्लीगी : सूत्रों ने बताया कि मदरसों और दरगाहों से जुड़े कई लोगों में इस वायरस के संक्रमण के फैलने की तीव्र आशंका है, क्योंकि तब्लीग से जुड़े कई सदस्य क्वारंटाइन केंद्रों में जाने से पहले अपने अन्य साथियों के साथ मेल मिलाप करने के अलावा विभिन्न मस्जिदों, मदरसों व दरगाहों में गए हैं। तब्लीग के ऐसे कई सदस्य भी कोविड-19 से प्रभावित पाए गए हैं जो निजामुद्दीन मरकज में नहीं गए थे। उन्होंने बताया कि बहुत से कोविड-19 पॉजिटिव पीड़ित अंत तक पूरी तरह स्वस्थ थे। बीमार होने के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो उनके संक्रमित होने का पता चला है।

- कई जमाती पढ़ाते भी हैं, अब मौलवियों, अध्यापकों और छात्रों को खोजा जा रहा
- 1200 मदरसे व 2000 दरगाह हैं जम्मू कश्मीर में, सभी की जांच शुरू कर हुई

मदरसों व दरगाहों को सैनिटाइज किया जा रहा

एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित सभी मदरसों और दरगाहों को सैनिटाइज डिकंटेमिनेट किया जा रहा है। इनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति न छूटे, इसके लिए राज्य पुलिस के खुफिया विंग को भी पूरी तरह सक्रिय किया गया है। इसके अलावा यह जहां भी हैं, वहां आसपास रहने वालों की जांच के साथ साथ उनसे भी मदरसा संचालकों व छात्रों का पता किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने छिपाई मरकज जाने की बात, केस दर्ज

जासं, नई दिल्ली

कोरोना के खिलाफ जंग में कांग्रेस के एक नेता की मनमानी ने परेशानी बढ़ा दी है। हॉट स्पाट बने निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज जाने की बात वह न केवल लगातार छिपाते रहे, बल्कि होम क्वारंटाइन किए जाने के बावजूद लोगों से मिलते-जुलते रहे। आखिर उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी मां और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इस नेता की पत्नी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पार्षद हैं।

पुलिस के अनुसार कांग्रेस नेता को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी उनके घर गए तो वह इलाके में घूम रहे थे। पूछताछ में उन्होंने यह नहीं बताया कि कहां-कहां गए और किस-किस से मिले। मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला गया तो पता चला कि वह निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में हुए धार्मिक कार्यक्रम में भी गए थे। बार-बार पूछने पर भी मरकज जाने की बात छिपाते रहे। कांग्रेस नेता की लापरवाही से क्षेत्र के लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। प्रशासन को चिंता हो रही है कि कांग्रेस नेता कई लोगों के संपर्क में आए होंगे। जनप्रतिनिधि के परिवार से जुड़े होने के कारण इनके संपर्क में कई निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी होंगे। इनकी पार्षद पत्नी भी कई लोगों से मिली होंगी। कई जगह इनकी ओर से राहत कार्य भी चलाया गया है। ऐसे में प्रशासन इस बात का पता लगाने में जुटा है कि कितने लोगों से ये संपर्क में आए।

- संक्रमण के बावजूद इलाके में घूमते पाए गए, पत्नी है पार्षद
- स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी नहीं दी सही जानकारी

दीनपुर गांव को किया गया सील

कोरोना के तीन मामले मिलने के बाद द्वारका जिले के दीनपुर गांव के करीब पचास घरों को सील कर दिया गया है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। प्रत्येक घर में लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसमें संदिग्ध पाए गए लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे।

निजामुद्दीन इलाके में बंद करवाई गईं सभी दुकानें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोरोना को लेकर निजामुद्दीन बस्ती की मरकज मस्जिद, निजामुद्दीन वेस्ट का जी व डी ब्लॉक, निजामुद्दीन बस्ती, निजामुद्दीन दरगाह को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तब्लीगी जमात से जुड़े तमाम लोग इन इलाकों में आते-जाते थे। यह इलाका संक्रमित हो चुका है। यहां पर संक्रमण से एक दुकानदार की मौत हो चुकी है। इस कारण यहां संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके के करीब छह हजार लोगों की स्क्रीनिंग करवाई है। इससे निकले परिणाम व संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस इलाके में लोग खाने-पीने की चीजें लेने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहां की मरकज में रहने वाले लोग पूरी कॉलोनी में आते-जाते थे।

नेपाल के जरिये भारत में कोरोना वायरस फैलाने की साजिश, बॉर्डर पर अलर्ट

जासं, पश्चिम चंपारण

नेपाल के जरिए भारत में कोरोना को फैलाने की साजिश का पता चला है। एसएसबी से मिली खुफिया सूचना के बाद पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिले के सिकटा बॉर्डर से लेकर वाल्मीकि नगर तक चौकसी बढ़ा दी गई है।

पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा पनकोटा स्थित एसएसबी 47वीं बटालियन के कमांडेंट ने बीते तीन अप्रैल को खुफिया सूचना दी थी कि नेपाल के परसा जिले के जगन्नाथपुर गांव निवासी जालिम मुखिया ने भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रची है। वह नेपाल से 40-50 कोरोना संदिग्धों को भारत में प्रवेश कराना चाहता। वह हथियार की अवैध सप्लाई एवं जाली नोटों के धंधे में भी संलिप्त रहा है।

एसएसबी की इस सूचना के बाद डीएम ने एसपी निताशा गुड़िया के अलावा बगहा पुलिस जिले के एसपी, नरकटियागंज के एसडीएम और सिकटा, मैनाटांड़, गौनाहा व बगहा दो के बीडीओ को अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत-नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। डीएम के आदेश के बाद एसपी निताशा गुड़िया ने नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती थानों को एसएसबी के साथ निगरानी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सिकटा से लेकर वाल्मीकि नगर तक बॉर्डर पर विशेष चौकसी रही।

एसपी निताशा गुड़िया ने कहा कि पत्र के आलोक में बॉर्डर के निकटवर्ती थानों को अलर्ट किया गया है। एसएसबी के साथ पुलिस गश्त कर रही है। वैसे भी बीते 24 मार्च से बॉर्डर सील है। किसी की आवाजाही नहीं हो रही है।

- नेपाल से 40-50 कोरोना संदिग्धों को प्रवेश कराने की तैयारी में हथियारों के धंधे से जुड़ा एक अपराधी
- एसएसबी की खुफिया सूचना पर पश्चिम चंपारण के डीएम ने एसपी व अन्य अधिकारियों को किया सचेत

गुजरात में तब्लीगी के बाद जमात-ए-शूरा ने बढ़ाया संकट

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

तब्लीगी जमात के बाद अब जमात-ए-शूरा ने गुजरात की पुलिस-प्रशासन की नींद उड़ा दी है। राज्य में जमात-ए-शूरा के करीब 11 सौ सदस्यों के आने की बात सामने आई है। इनमें से चार लोग कोरोना से संक्रमित भी पाए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने बताया कि दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से गुजरात में आए, 130 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इन सभी को क्वारंटाइन कर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। झा ने बताया कि भरुच में शूरा जमात से आए चार लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। शूरा के 1095 लोग गुजरात आए हैं प्रशासन को इसकी जानकारी भी मिली जिसके बाद से सरकार व प्रशासन काफी चौकन्ना है।

जिन चार लोगों को संक्रमित पाया गया है, वो सभी तमिलनाडु से ट्रेन के जरिए अंकलेश्वर पहुंचे तथा वहां से बस के जरिए भरुच पहुंचे। 12 से 17 मार्च तक वे मस्जिद में ठहरे तथा बाद में पास के गांव ईखर की एक मस्जिद में चले गए। प्रशासन ने ईखर गांव की सात किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव आमोद, आच्छण, सुथोदरा, तेलोद,मातर, दांडा, दोरी, कोठी, करेणा, तथा भरुच तहसील के कंबोली, सीमिलिया किसानाद व पालेज गांव को 23 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया। पुलिस महानिदेशक झा ने बताया कि गुजरात में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक के 164 अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं।

- राज्य में शूरा के 1100 सदस्यों के आने की खबर, इनमें से चार कोरोना संक्रमित
- तब्लीगी जमात से अलग हुए धड़े ने किया था जमात-ए-शूरा का गठन

क्या है जमात-ए-शूरा

तब्लीगी जमात के ग्लोबल हेडक्वार्टर निजामुद्दीन मरकज के अमीर मौलाना जुबैर के निधन के बाद मौलाना साद मरकज के अमीर बन बैठे तो मौलाना जुबैर के पुत्र जुहेरुल हसन ने तुर्कमान गेट पर मौलाना इब्राहिम के साथ मिलकर जमात ए शूरा का गठन किया था। मौलाना साद व जुहेरुल हसन में मरकज पर कब्जे को लेकर भारी तनातनी है तथा लॉकडाउन के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों के चलते साद के कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद मरकज की कमान भी जमात-ए-शूरा के हाथ में आ सकती है।

चिर शांति में हीरानंद

संगीत के जरिये शिष्यों को सिखा गई जिंदगी का पाठ

याद रहेंगी बेगम की बिट्टन